EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- NIKHIL RANJAN

Useful For Prelims

Date: 25 December 2025

तैयारी | ओलंपियन मिस्टर जैक की अगुवाई में मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और नमिता ने राज्य में तीन जगहों पर डैम का किया निरीक्षण

बांका के ओढ़नी डैम में बनेगी पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी

पटना, मुख्य संवाददाता। बांका जिले की ओढ़नी डैम में बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। वाटर स्पोर्ट्स के विकास की सम्भावनाओं पर बुधवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस बात की घोषणा की। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के साथ मुलाकात के बाद दोनों प्रदेशों के बीच राज्य में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के आपसी तालमेल और सहयोग पर सहमति बनी थी। इसी सिलसिले में भोपाल स्थित इंडियन केनोइंग एंड क्याकिंग एसोसिएशन के द्वारा बिहार में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के चयन के लिए कनाडा के ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मिस्टर जैक की अगुवाई में मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नमिता की एक टीम यहां भेजी गई। उन्होंने कहा कि तीन दिनों तक विशेषज्ञों की टीम ने सासाराम का दुर्गावती डैम, जमुई का गढी डैम, बांका का ओढ़नी डैम तथा नवादा का हरदिया डैम का सघन निरीक्षण किया। बांका स्थित ओढ़नी डैम को कनाडा से आए विशेषज्ञ मिस्टर जैक ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए सबसे उपयुक्त पाया। जैक ने कहा कि बांका का ओढ़नी डैम वाटर स्पोर्ट्स के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक है। यह डैम ना सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स अकादमी खोलने और प्रशिक्षण के लिए बेहतर है बल्कि यहां पर केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भीकरायी जा सकती है। फरवरी माह में मिस्टर जैक बिहार आयेंगे और यहां के प्रतिभावान खिलाडियों के चयन, उनके प्रशिक्षण और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए जरूरी उपकरणों और जेटिस जैसी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में सहयोग करेंगे। इस वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त ,खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उपकरण से लेकर उनके रहने तक की स्तरीय व्यवस्था की जाएगी जिससे बिहार के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शनकर सकेंगे। बैठक में ऑलंपियन जैक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बांका जिले की ओढ़नी डैम में नौका विहार का आनंद उठाते पर्यटक। ● फाइल फोटो

- राज्य की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने की घोषणा
- कहा, कनाडा से आए विशेषज्ञजैक ने वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए डैम को उपयुक्त पाया
- यहां केनोइंग और रोइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हो सकती है

लिस्ट ए मैच में विराट ने 330 पारियों में हासिल किया मुकाम | उपलब्धि | पंद्रह साल बाद विजय हजारे ट्राफी में वापसी, जड़ा शतक

कोहली ने सबसे तेज 16000 रन बनाकर सचिन का रेकार्ड तोड़ा

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

विराट कोहली ने बुधवार को विजय हजारे ट्राफी में 58वां लिस्ट ए शतक जड़ा। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 15 साल बाद वापसी की है। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16000 रन पूरे करके दिग्गज सचिन तेंदुलकर का रेकार्ड तोड़ दिया। उन्होंने 330 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की, जबकि सचिन 391 पारियों में इस मुकाम पर पहुंचे थे। बंगलुरु में बीसीसीआइ के सेंटर आफ एक्सिलेंस ग्राउंड में बुधवार को दिल्ली की तरफ से उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन की पारी खेली। उन्होंने 14 चौके और तीन छक्के भी लगाए।

कोहली भले ही 15 साल बाद विजय हजारे ट्राफी में खेल रहे हों, लेकिन उनका रेकार्ड इस टूर्नामेंट में शानदार रहा है। इस प्रमुख घरेलू एक दिवसीय प्रतियोगिता में 13 मैचों में 68.25 के औसत और 106 के स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

क्या होता है लिस्ट ए क्रिकेट

लिस्ट ए क्रिकेट सीमित ओवर प्रारूप का खेल है, जिसे एक ही दिन में खत्म किया जाता है। दोनों टीमों को अधिकतम 50 ओवर तक खेलने का मौका दिया जाता है। यह मैच आमतौर पर आठ घंटे या उससे कम समय में खत्म हो जाता है। भारत में लिस्ट ए क्रिकेट के रूप में देवधर ट्राफी और विजय हजारे ट्राफी खेला जाता है।

कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को मैच सेंटर आफ एक्सीलेंस में कराने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ महीने भगदड़ के कारण सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती गई। मैच के दौरान कोहली को अपनी टीम (दिल्ली) के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते देखा गया। वे जूनियर खिलाड़ियों को समझाते दिखे। जब आंध्र प्रदेश के बल्लेबाजों ने दिल्ली के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की धुनाई की, तो उन्हें सलाह भी दी। कोहली ने आस-पास उत्साह का माहौल बनाने की कोशिश भी की।

दूसरी ओर, आंध्र के खिलाड़ियों और अधिकारियों ने विराट का आटोग्राफ भी लिया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। मैच के बाद आंध्र के लिए शतक लगाने वाले रिकी भुई ने बताया कि उनके लिए मैदान पर कोहली के साथ या खिलाफ खेलना सपना था। आंध्र के सभी क्रिकेटर इस मौके से बहुत खुश थे।

Jansatta Page No-20

शिक्षा मंत्रालय ने एक गंभीर चुनौती माना | तैयारी | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान बनाएगा भविष्य की राह

हर वर्ष 50 लाख विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में होते हैं विफल

सुशील राघव
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

देश में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में हर साल करीब 50 लाख विद्यार्थी विफल हो जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे एक गंभीर चुनौती मानते हुए इन विद्यार्थियों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की है। इसके लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह इन विद्यार्थियों तक पहुंचे और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करे।

शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, देश भर के सभी बोर्ड में दसवीं और बारहवीं में दो से सवा दो करोड़ विद्यार्थी हर वर्ष परीक्षा देते हैं। इनमें से करीब 50 लाख विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सफल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने का काम एनआइओएस को दिया जा रहा है।

एनआइओएस अगली परीक्षा के बाद यह काम करेगा। देश में आठवीं तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 93 फीसद है जो दसवीं में कम होकर 70 फीसद और 12वीं तक 58 फीसद तक हो जाता है। देश का नौवीं से 12वीं तक जीईआर 68 फीसद है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि हम समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली राशि को भी एनआइओएस के शुल्क से जोड़ने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि बोर्ड परीक्षाओं में सफल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। एनआइओएस इन विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही नहीं छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे देश का समग्र जीईआर बढ़ेगा।

वित्तीय जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे छात्र

देश में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के मामले में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, इसको लेकर किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि वित्तीय जरूरतों की वजह से सबसे अधिक लड़के पढ़ाई को बीच में छोड़ते हैं। वहीं, लड़कियों की पढ़ाई घर में काम कराने के लिए बीच में ही बंद करा दी जाती है। लड़कों पर घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने का बोझ होता जिस वजह से वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं।

हर खंड में बनेगा एक एनआइओएस केंद्र

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में स्कूली शिक्षा के अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य से देश के हर खंड में एनआइओएस का एक केंद्र खोलने के बारे में विचार किया जा रहा है।

यह केंद्र हर खंड में खोलने जाने वाले पीएम श्री विद्यालयों में शुरू होंगे। यहां से उन विद्यार्थियों तक पहुंच बनाई जाएगी जो किन्हीं भी कारणों से पढ़ाई छोड़ रहे हैं।

Jansatta Page No-12

पुतिन के भारत दौरे के बाद इंदौर के शख्स की पहल | अद्भुत | दोनों देशों की दोस्ती के प्रति अनूठे तरीके से सम्मान जताया

पीतल के पन्नों पर उकेरा गया रूस का संविधान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के प्रति अनूठे तरीके से सम्मान जताने के लिए इंदौर में पीतल के पन्नों पर रूस का संविधान उकेरा गया है। इस पहल को स्थानीय निवासी लोकेश मंगल ने अंजाम दिया है जो पीतल के पन्नों पर पुस्तकें छपवाने के लिए मशहूर हैं। मंगल ने बुधवार को कहा कि भारत और रूस पुराने मित्र हैं। मैंने दोनों देशों की दोस्ती के सम्मान में रूस के संविधान को पीतल पर उकेरने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि रूसी संविधान के अंग्रेजी संस्करण के नौ अध्यायों और 137 अनुच्छेदों को पीतल के 56 पन्नों पर उकेरा गया है और इस काम में आधा किलोग्राम पीतल लगा है। पीतल के पन्नों की इस किताब को कारीगरों ने आठ घंटे में मशीनों की मदद से तैयार किया है। मंगल ने बताया कि वे रामायण, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों को भी पीतल के पन्नों पर छपवा चुके हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में पीतल को शुभ माना जाता है। इसलिए मैं पीतल के पन्नों पर ग्रंथ तैयार कराता हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में भारत का दो दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के नए कदमों की घोषणा की थी तथा स्वास्थ्य, गतिशीलता और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

इससे पहले उन्होंने 2023 में 193 देशों के संविधानों की 57 किलो की किताब और भारतीय संविधान सभा का पीतल से बना माडल तैयार किया था। उनके द्वारा बनाए गए कृतियों को न केवल भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। इसके अलावा वे भारत के 760 जिलों से संबंधित दस्तावेजों की 760 किताबों के मुख्य पृष्ठों को जारी कर चुके हैं। उन्होंने किताब में विभिन्न शहरों के हृदयस्थल, न्यायालय चिह्न, पुलिस चिह्न, शैक्षणिक संस्थान, वन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, उद्योग, स्वास्थ्य के साथ ही महत्त्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है।

उन्होंने बताया कि रूसी संविधान के अंग्रेजी संस्करण के नौ अध्यायों और 137 अनुच्छेदों को पीतल के 56 पन्नों पर उकेरा गया है और इस काम में आधा किलोग्राम पीतल लगा है। पीतल के पन्नों की इस किताब को कारीगरों ने आठ घंटे में मशीनों की मदद से तैयार किया है।

राष्ट्रपति पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में भारत का दो दिवसीय दौरा किया था। मंगल ने बताया कि वे रामायण, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों को भी पीतल के पन्नों पर छपवा चुके हैं। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में पीतल को शुभ माना जाता है।

Jansatta Page No-14

भारतीय खिलाड़ियों में बढ़ा शक्तिवर्धक दवाओं का चलन

हिमांशु अग्निहोत्री

चिंताजनक

डोपिंग एक गंभीर समस्या है, जो खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है तथा खेल की निष्पक्षता को चुनौती देती है। डोपिंग का अर्थ है प्रतिबंधित पदार्थों या विधियों का उपयोग कर प्रदर्शन को कृत्रिम रूप से शक्ति बढ़ाना। भारत में यह मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि विश्व एंटी-डोपिंग एजंसी (वाडा) की रपट में भारत लगातार डोपिंग उल्लंघनों में शीर्ष स्थान पर रहा है। हालांकि यह चिंता का विषय है क्योंकि अगर सुधार नहीं हुआ और भारत 2036 ओलंपिक की बोली लगाता है तो यह आंकड़े गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। ये दावेदारी में बाधा बन सकते हैं और भारत का ओलंपिक मेजबानी का सपना अधूरा रह सकता है।

संसद ने अगस्त 2025 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। यह विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और 12 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम में संशोधन कर विश्व डोपिंग रोधी एजंसी के मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना है। 2022 का मूल अधिनियम सरकारी हस्तक्षेप के कारण लागू नहीं हो सका। इससे भारत पर वाडा प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा था। संशोधन से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी को जांच, प्रवर्तन और संचालन में पूर्ण स्वायत्तता मिली है। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं, सभी डोप नमूने लैब भेजने के लिए वाडा मान्यता अनिवार्य, अंतरराष्ट्रीय कोड की परिभाषाएं भारतीय कानून में शामिल, खिलाड़ियों पर केवल खेल प्रतिबंध लगे न कि कोई आर्थिक दंड तथा वाडा को खेल पंचाट न्यायालय में सीधी अपील का अधिकार।

भारत में डोपिंग जांच का दायित्व मुख्य रूप से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) पर है। नाडा भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है और देश भर में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। वाडा की 2024 डोपिंग रोधी उल्लंघन (एडीआरवी) रपट के अनुसार, भारत ने डोपिंग उल्लंघनों में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। नाडा ने 2024 में कुल 7,113 नमूने एकत्र किए, जिनमें 6,576 मूत्र और 537 रक्त जांच के नमूने शामिल थे। इनमें से 260 नमूने पाजिटिव मिले, जो 3.6 फीसद पाजिटिविटी दर को दर्शाते हैं। यह दर उन देशों में सबसे अधिक है जो 5,000 से अधिक परीक्षण करते हैं।

प्रमुख खेलों में एथलेटिक्स में सबसे अधिक जांच (1,862) हुईं, उसके बाद भारोत्तोलन (664) और कुश्ती (414) में एकत्र किए गए। भारत की तुलना में, फ्रांस में 91, इटली में 85 और रूस व अमेरिका में 76 मामले थे। 2023 में भारत में 213 पाजिटिव मामले थे, जो 2024 में बढ़कर 260 हो गए। नाडा का कहना है कि यह वृद्धि जांचों की संख्या बढ़ने के कारण है, न कि डोपिंग के बढ़ने से। 2019 में नाडा ने मात्र 4,004 नमूने लिए थे, जो 2024 में दोगुने से अधिक हो गए। पाजिटिविटी दर भी 2019 के 5.6 फीसद से घटकर 3.6 फीसद हो गया है। 2025 में नाडा ने 7,068 परीक्षण किए, जिनमें 110 पाजिटिव मामले (1.5 फीसद रेट) सामने आए। नाडा ने 2025 के लिए 7,751 नमूने एकत्र किए। सुधार के प्रयासों में नाडा ने 2024 में 280 जागरूकता कार्यक्रम किए, जिनमें 37,000 खिलाड़ी शामिल हुए। साल 2025 में 329 कार्यक्रम हुए, जिनमें वेबिनार, सेमिनार और डिजिटल अभियान शामिल हैं। हालांकि डोपिंग के बढ़ते मामलों पर रपट आने के बाद अभी खेल मंत्रालय से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है।

आइ नो योर मेडिसिन एप से एथलीट दवाओं में प्रतिबंधित पदार्थ जांच सकते हैं। डोपिंग जांच एक सख्त और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो वाडा के मानकों पर आधारित है। यह प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता से बाहर दोनों में होती है। खिलाड़ियों का चयन रैंडम, लक्षित या इंटेलिजेंस पर आधारित होता है।

प्रक्रिया की शुरुआत होती है डोपिंग नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) द्वारा एथलीट को सूचित करने से। एथलीट को तुरंत डोपिंग नियंत्रण केंद्र (डीसीएस) जाना होता है। यहां एथलीट एक सीलबंद पात्र चुनता है और मूत्र नमूना देता है, जो दो भागों (ए और बी) में विभाजित होता है। रक्त नमूना फ्लेबोटामिस्ट लेता है। नमूने को वाडा अधिकृत प्रयोगशाला में भेजा जाता है। प्रयोगशाला में उच्च तकनीकों से प्रतिबंधित पदार्थों की जांच होती है। वाडा की प्रतिबंधित सूची में स्टेरायड्स, स्टिमुलेंट्स, डाइयूरेटिक्स आदि शामिल हैं।

अगर ए नमूना पाजिटिव है, तो एथलीट बी सैंपल की जांच मांग सकता है। एथलीट सफल (पास) होते हैं अगर उनके सैंपल में कोई प्रतिबंधित पदार्थ या इसका मेटाबोलाइट नहीं पाया जाता। सफलता के लिए एथलीट को वाडा की प्रतिबंधित सूची का ज्ञान होना चाहिए। दवाएं चेक करनी चाहिए और पूरक आहार का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। विफल (फेल) होने के कारण मुख्यतः प्रतिबंधित पदार्थों का जानबूझकर या अनजाने में उपयोग है। जानबूझकर उपयोग में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्टेरायड्स लेना शामिल है। अनजाने में प्रदूषित पूरक आहार या दवाओं से होता है। अगर पाजिटिव, तो एडीआरवी घोषित होता है और प्रतिबंध लगते हैं। 2-4 साल की निलंबन, जुर्माना, या आजीवन प्रतिबंध। भारत में कई मामले प्रदूषित पूरक आहार से जुड़े हैं। प्रमुख प्रभावित खिलाड़ी, जो डोपिंग उल्लंघनों से प्रभावित हुए हैं। हैमर थ्रो में मंजू बाला 2014 की एशियाई खेलों में पदक जीत चुकी हैं। मंजू डोपिंग जांच में विफल रहीं। इस कारण उन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जो 2024 से प्रभावी है। मैराथन/क्रास-कंट्री की एथलीट रेशमा दत्तू केवाते मेथाक्सी पालीइथाइलीन ग्लाइकाल-एपोएटिन बीटा और ईपीओ के लिए पाजिटिव पाई गईं, जो मई 2024 से प्रभावी हैं। रेशमा पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दो सौ मीटर स्प्रिंटर सुम्मी क्लोमिफेन के लिए पाजिटिव पाई गई थीं। अंडर-23 विजेता और पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची ऋतिका हुड्डा (कुश्ती) 2025 में पाजिटिव जांच के बाद निलंबित की गईं। हालांकि इस जांच से वे खुश नहीं थीं और उन्होंने कहा था कि वे बी सैंपल के लिए नमूने देने पर विचार करेंगी। धावक परवेज खान भी जांच में विफल हुए। गुरप्रीत सिंह (कुश्ती), मोहन सैनी (एथलेटिक्स), हेमराज गुर्जर (क्रास-कंट्री, एथलेटिक्स) में विफल हुए। हालांकि डोपिंग की जद में कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी भी इस जद में फंस चुके हैं। इनमें यूसुफ पठान 2017 में, दिग्गज आस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न 2003 विश्व कप के दौरान और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग शामिल हैं।

Jansatta Page No-7

आकाश मिसाइलों के एडवांस वर्जन का किया गया सफल परीक्षण

मिसाइल परीक्षण का दृश्य। डीआरडीओ

जासं, बालेश्वर: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 'नेक्स्ट जेनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम' यानी आकाश-एनजी के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में हुए परीक्षणों में मिसाइल ने सभी मानकों को पूरा किया। इन परीक्षणों के साथ ही यह अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना और वायु सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, वायु सेना को बधाई दी है। अगर इसे पाकिस्तान या चीन की सीमाओं के पास तैनात किया जाता है तो यह 70-80 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है।

Dainik Jagaran Page No-19

इसरो का ऐतिहासिक मिशन

'बाहुबली' प्रक्षेपण यान ने अमेरिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

क्रिसमस से पहले, एक ऐतिहासिक मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सबसे भारी प्रक्षेपण यान 'एलवीएम-3 एम6' ने एक अमेरिकी संचार उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में बुधवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जिसे अंतरिक्ष एजंसी प्रमुख ने देश के लिए तोहफा करार दिया। प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 एम6 ने 6,100 किलो वजनी 'ब्लूबर्ड ब्लाक-2' उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।

'ब्लूबर्ड ब्लाक-2' मिशन का उद्देश्य उपग्रह के जरिए सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। यह नेटवर्क कहीं भी, कभी भी, सभी के लिए 4जी और 5जी वायस-वीडियो काल, संदेश, स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 एम6 को अत्यधिक भार ले जाने की उसकी क्षमता के कारण 'बाहुबली' नाम भी दिया गया है। इसरो ने कहा कि 'एलवीएम3-एम6' ने सटीक प्रक्षेपण प्रक्रिया के तहत उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। यह मिशन 'न्यूस्पेस इंडिया

बाकी पेज 8 पर

इसरो की नई उपलब्धि।

वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका मजबूत

पेज 8

Jansatta Page No11

भारत ने रचा इतिहास, 'बाहुबली' ने भेजा दुनिया का सबसे वजनी सेटेलाइट

6100 किलो वजन वाले अमेरिकी उपग्रह को 15 मिनट में कक्षा में किया स्थापित

उपलब्धि

- इसरो का अब तक का सबसे भारी राकेट है एलवीएम3-एम6
- इसी राकेट से गगनयान मिशन को दिया जाएगा अंजाम

श्रीहरिकोटा, प्रेट : नए साल के आगमन से पहले भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रच दिया है। 'बाहुबली' के नाम से मशहूर इसरो के सबसे भारी प्रक्षेपण यान एलवीएम3-एम6 ने बुधवार को एक अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लाक-2 को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस उपग्रह का वजन 6100 किलोग्राम है।

भारत की धरती से लांच किया गया यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। जिस राकेट से इस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, उसी से भारत के गगनयान मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख ने इसे देश के लिए क्रिसमस का उपहार बताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो की इस उपलब्धि की सराहना की है।

लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद ब्लूबर्ड ब्लाक-2 उपग्रह प्रक्षेपण यान से अलग हो गया और इसे सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इससे मिशन कंट्रोल सिस्टम में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्लू बर्ड ब्लाक-2 का उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इससे हर किसी को, हर जगह, हर समय 4जी और 5जी वायस और वीडियो काल, टेक्स्ट मैसेज, स्ट्रीमिंग और डाटा की सुविधा मिलेगी। इसरो ने बताया कि न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका की एएसटी स्पेसमोबाइल के बीच हुए एक वाणिज्यिक समझौते के तहत संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की वाणिज्यिक इकाई है। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एलवीएम3-एम6 प्रक्षेपण यान ने ब्लूबर्ड-ब्लाक 2 उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर न्यू स्पेस इंडिया और एएसटी स्पेसमोबाइल को बधाई देता हूं।

> एलवीएम3-एम6 का प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत की भारी पेलोड प्रक्षेपण की क्षमता को दिखाता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी भूमिका को और मजबूत करता है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
> -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एलवीएम3-एम6 के सफल प्रक्षेपण पर टीम इसरो को बधाई। दुनियाभर में बेहतर संचार उपलब्ध कराने के लिए जिस अमेरिकी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, वह हमारे विज्ञानियों की क्षमता को दिखाता है। यह भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक गंतव्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करता है।
-अमित शाह, गृह मंत्री

Dainik Jagaran Page No-19

मिशन में एलवीएम-3 की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार कामयाब रहा

अमेरिकी उपग्रह 'ब्लूबर्ड' को इसरो ने बेहद सटीकता से स्थापित किया

श्रीहरिकोटा, एजेंसी। इसरो ने क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसके 'बाहुबली' रॉकेट एलवीएम3-एम6 ने 6,100 किलोग्राम वजनी अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह अब तक भारतीय प्रक्षेपण यानों द्वारा हासिल सबसे बेहतर सटीकता है।

रॉकेट ने सुबह 8:55 बजे दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। लगभग 15 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह रॉकेट से अलग हुआ और कक्षा में स्थापित हो गया। इसके साथ ही मिशन नियंत्रण कक्ष में उत्साह का माहौल बन गया। इसरो के अनुसार, उपग्रह को 520 किलोमीटर की निर्धारित कक्षा के बजाय 518.5 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया।

इसरो ने इस सटीकता को 'टेक्स्टबुक लॉन्च' बताया। इसका अर्थ है कि प्रक्षेपण पूरी तरह योजना के अनुसार, बिना किसी तकनीकी चूक के, तय समय और सटीकता से सफलतापूर्वक पूरा हुआ। यह मिशन न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और एएसटी स्पेसमोबाइल के बीच हुए वाणिज्यिक समझौते के तहत पूरा किया गया। यह इसरो की वाणिज्यिक इकाई है।

520 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करना लक्ष्य था

एलवीएम-3 की मांग बढ़ी

एनएसआईएल प्रमुख

इसरो की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के प्रमुख पी मोहन ने कहा कि एलवीएम-3 की लगातार सफलता के बाद वैश्विक स्तर पर इसकी मांग बढ़ी है। उन्होंने बताया कि 2026-27 से हर साल छह से दस मिशनों के लिए अनुरोध मिल रहे हैं।

उपग्रह लॉन्च करने वाला भरोसेमंद बना भारत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह मिशन भारत से अब तक के सबसे भारी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता से यह साबित हुआ है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपग्रह लॉन्च करने वाले बड़े और भरोसेमंद देशों में शामिल हो गया है तथा विदेशी कंपनियां भी भारत पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। गगनयान जैसे भविष्य के अभियानों की नींव भी सुदृढ़ हुई है।

> यह मिशन भारत की अंतरिक्ष विशेषज्ञता को व्यावसायिक सफलता में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत को अंतरिक्ष तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को मजबूती देती है। – **अमित शाह**, केंद्रीय गृह मंत्री

> यह सफलता उन पीढ़ियों की नींव पर खड़ी है, जिन्होंने वैज्ञानिक सोच को देश को नई ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम माना। –**राहुल गांधी**, कांग्रेस नेता

> यह उपलब्धि भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को बड़ी मजबूती देगी। – **जितेंद्र सिंह**, केंद्रीय मंत्री

गगनयान मिशन को लेकर भरोसा बढ़ा : इसरो चीफ इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, एलवीएम-3 एम6 रॉकेट से उपग्रह के सफल प्रक्षेपण ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर भरोसा और मजबूत किया है। एलवीएम-3 वही रॉकेट है, जिसे गगनयान मिशन के लिए तय किया गया है। इससे गगनयान कार्यक्रम के लिए जरूरी विश्वसनीयता साबित होती है।

अब तक की सबसे बेहतर सटीकता : नारायणन ने कहा, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को तय कक्षा में बेहद सटीकता से स्थापित किया गया है। यह अब तक भारतीय प्रक्षेपण यानों द्वारा हासिल की गई सबसे बेहतर सटीकता है। रॉकेट की विश्वसनीयता शत-प्रतिशत रही। अंतरिक्ष मलबे की स्थिति को देखते हुए समय में एक मिनट का बदलाव किया गया।

Hindustan Page No-24

उपलब्धि | चेन्नई के इंजीनियरिंग छात्रों ने दुर्गम गांवों तक इंटरनेट सेवा देने का प्रोजेक्ट बनाया, नासा ने 'मोस्ट इंस्पिरेशनल' प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया

भारतीय छात्रों के 'स्वदेशी इंटरनेट उपग्रह' को नासा पुरस्कार

चेन्नई, एजेंसी। चेन्नई के इंजीनियरिंग छात्रों के एक दल ने दुनियाभर के 18000 से अधिक तकनीकी प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ते हुए नासा पुरस्कार जीता है। उनका प्रोजेक्ट स्वदेशी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने पर बनाया गया है। अब यह प्रोजेक्ट इसरो को तकनीकी परीक्षण के लिए सौंपने की तैयारी है।

नासा के 'इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज 2025' के तहत चेन्नई के छात्रों ने देश के दूरस्थ और दुर्गम गांवों तक सस्ती और उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने का प्रोजेक्ट तैयार किया। टीम के सदस्य रहे एसआरएम ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के छात्र प्रशांत गोपालकृष्णन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को उन्होंने 'फोटोनिक्स ओडिसी' और 'आकाश नेट' नाम दिया। बताया कि नासा ने इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और तकनीकी क्षमता को देखते हुए इसे चयनित शीर्ष दस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। नासा ने इस प्रोजेक्ट को 'मोस्ट इंस्पिरेशनल' यानी सबसे अधिक प्रेरक करार दिया है। बताया कि अब वे इस प्रोजेक्ट को तकनीकी दस्तावेजीकरण, पेटेंट और परीक्षण के लिए इसरो के समक्ष रखने वाले हैं।

प्रशांत ने कहा कि नासा की मुहर लग जाने के बाद अब उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट को सार्वजनिक रूप से प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने में सांस्थानिक मदद मिल सकेगी। बताया कि टीम में राजलिंगम एन, रश्मि मेनन, शक्ति संजीव कुमार, धीरज कुमार और मनीष वर्मा शामिल थे। नासा की ओर से प्रतिवर्ष 'इंटरनेशनल स्पेस ऐप्स चैलेंज' नाम से दुनिया के सबसे बड़े हैकाथन का आयोजन किया जाता है। 2012 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। इसमें दुनियाभर से छात्र जनोपयोगी तकनीकी परियोजनाएं बनाकर भेजते हैं। इसका मकसद नासा के उपग्रहों, टेलीस्कोप व मिशन से मिले निशुल्क और ओपन डेटा का इस्तेमाल करके अन्वेषण को बढ़ावा देकर धरती व अंतरिक्ष के लिए जरूरी समाधानों की तलाश करना है।

18 हजार से अधिक प्रोजेक्ट दुनियाभर से नासा को मिले

10 शीर्ष प्रस्तावों में रहा चेन्नई के छात्रों का यह प्रोजेक्ट

इसरो से प्रेरित है 'आकाश नेट'

टीम के सदस्य रहे एसआरएम ईश्वरी इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र प्रशांत ने बताया कि उनका यह प्रोजेक्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कार्यशैली से प्रेरित है। इसी कार्यशैली ने उन्हें कम लागत में वैश्विक गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम प्रोजेक्ट तैयार करने की प्रेरणा दी। इसका लक्ष्य भारत के गांवों तक उच्च गति इंटरनेट सुविधा देकर शहरों और गांवों के बीच डिजिटल अंतर को खत्म करना है।

ऐसे तैयार किया प्रोजेक्ट

छह सदस्यीय टीम में चार छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन और दो कंप्यूटर साइंस से रहे। ईसी के छात्रों ने जहां हार्डवेयर व संचार प्रारूप तैयार करने पर ध्यान दिया, वहीं ईसी छात्रों ने सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी संभाली। दो से तीन माह में उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ।

स्वदेशी मॉडल से घटती है लागत : प्रशांत ने कहा कि अधिकतर वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट प्रणालियों में व्यावसायिक प्रारूपों को महत्व दिया जाता है। उनके हार्डवेयर विदेशों में बनाए जाते हैं। आयातित सामग्री और तकनीक के चलते भारत में इनकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन्होंने अपने मॉडल में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा और भारतीय सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी लागत कम हुई।

Hindustan Page No-24

रुपये को संभालने के लिए आगे आया आरबीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आरबीआइ ने रुपये की बढ़ती अस्थिरता और बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी को देखते हुए एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश की है। इसके लिए केंद्रीय बैंक की तरफ से 13 जनवरी 2026 को 10 अरब डालर (लगभग 90,000 करोड़ रुपये) के डालर और भारतीय रुपये में क्रय-बिक्री करने का स्वैप आपरेशन आयोजन करने का एलान किया है। यह तीन साल की अवधि का स्वैप होगा यानी अभी बैंक आरबीआइ को डालर बेचेंगे और बदले में रुपये लेंगे। लेकिन तीन वर्ष बाद बैंक रुपये दे कर डालर वापस खरीद सकेंगे। इससे बैंकिंग सिस्टम में बड़ी मात्रा में नकदी बढ़ेगी, जिससे ब्याज दरों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी और बैंक ज्यादा कर्ज बांट कर अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद करेंगे।

एक दिन पहले ही आरबीआइ ने ओपन मार्केट आपरेशंस (ओएमओ) के जरिये दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का भी एलान किया है। यह खरीद चार बराबर किस्तों में, 29 दिसंबर 2025, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 22 जनवरी 2026 को 50-50 हजार करोड़ रुपये की होगी। इस तरह से दो दिनों में आरबीआइ ने कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम में करीब तीन लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त डालने का इंतजाम कर दिया है। उक्त दोनों कदम भारतीय रुपये को भी स्थिर रखने में मददगार साबित होंगे। पिछले एक महीने से डालर के मुकाबले भारतीय रुपया काफी दबाव में रहा है। एक डालर के मुकाबले रुपये की कीमत 91 के स्तर को छू चुका है। विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पैसा निकालने, अमेरिकी व्यापार नीतियों की अनिश्चितता जैसी वजहों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। आरबीआइ की तरफ से रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सक्रियता बढ़ा दी गई है।

- 10 अरब डालर का स्वैप आक्शन और दो लाख करोड़ रुपये की नकदी डालेगा
- बैंकों से आरबीआइ डालर खरीदेगा, तीन वर्ष बाद बैंक फिर से खरीद सकेंगे अमेरिकी मुद्रा

आरबीआइ पहले भी उठा चुका है कई बड़े कदम

आरबीआइ ने 2025 में रुपये की स्थिरता के लिए कई कदम उठाए हैं। दिसंबर की शुरुआत में भी पांच अरब डालर का तीन साल का स्वैप आक्शन (16 दिसंबर 2025 को आयोजित) और एक लाख करोड़ रुपये के ओएमओ की घोषणा की गई थी। आरबीआइ के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में अब तक ओएमओ, स्वैप व अन्य तरीकों से आरबीआइ ने बैंकिंग सिस्टम में नौ से दस लाख करोड़ रुपये की राशि डाली है।

Dainik Jagaran Page No-17

बिहार के आदर्श ने स्टार्टअप से बदली हजारों छात्रों की जिंदगी

इनसे सीखें

पटना, मुख्य संवाददाता। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट प्रखंड अंतर्गत पुरैना सरोत्र गांव के रहने वाले 18 वर्षीय आदर्श कुमार को ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से लंदन में इसी साल एक अक्टूबर को सम्मानित किया गया। इसकी राशि लगभग 90 लाख रुपये है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से 11 हजार छात्रों ने भाग लिया था। यह पहली बार है जब किसी भारतीय छात्र ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। इसके अलावा, आदर्श को उनके स्कूल की ओर से दो वर्षों के लिए 30 लाख रुपये की 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति भी मिली है।

ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, जिसे वार्की फाउंडेशन की ओर से Chegg.org के सहयोग से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक वार्षिक 1 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन असाधारण छात्रों को सम्मानित करता है, जो शिक्षा, अपने साथियों और समाज पर सकारात्मक व महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

आर्थिक कारणों से अधूरे रहे सपने पर हार नहीं मानी

वर्ष 2022 में उन्होंने आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा का रुख किया था। लेकिन आर्थिक कारणों से यह सपना अधूरा रह गया। उस समय कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन आदर्श ने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना। आईआईटी की तैयारी छोड़ने के बाद आदर्श ने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उनके तीन स्टार्टअप पूरी तरह असफल रहे। लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वर्ष 2023 में स्किलजो नाम से एक नया स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप का उद्देश्य स्कूली छात्रों को 21वीं सदी के उद्यमिता कौशल, नवाचार और नेतृत्व के गुर सिखाना है। स्किलजो के माध्यम से अब तक देशभर के करीब 20 हजार स्कूली बच्चों को मुफ्त में उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खास बात यह है कि इस स्टार्टअप की पार्टनरशिप देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी, मद्रास और मुंबई के साथ है। स्किलजो से जुड़े कई छात्रों ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के समर प्रोग्राम में भी भाग लिया है, जहां उन्हें पूर्ण स्कॉलरशिप मिली। स्टार्टअप के तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी आधुनिक जानकारियां भी दी जाती हैं, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

- 12वीं के छात्र आदर्श को लंदन में ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से सम्मानित किया गया

बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से सम्मानित छात्र आदर्श के साथ बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह।

सीएम से आदर्श ने की मुलाकात

ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज से सम्मानित आदर्श कुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट की। आदर्श कुमार ने शिक्षा, कौशल विकास और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने कार्यों व अनुभवों को साझा करते हुए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। आदर्श ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा व महिला सशक्तिकरण को मिली प्राथमिकता के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जताई। आदर्श के साथ बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह भी मौजूद थे।

Hindustan Page No-8

पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद

साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आए हो निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे... मगर अफसोस, आज विरले ही लोग होंगे, जो देश और समाज के बारे में गंभीरता से सोचते होंगे? वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सरकार में आम जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, लेकिन असलियत में हमारे अधिकारी कितने जवाबदेह बने, यह कोई रहस्य नहीं है। आज भी लालफीताशाही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, जिसको खत्म करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कोशिश जमीन पर नहीं दिख रही।

दरअसल, हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। यह सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ऐसे में, सुशासन की ओर भारत भला कैसे बढ़ सकेगा? आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जवाबदेह शासन-व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लिहाजा, जब तक नेताओं, नौकरशाहों और अन्य हितधारकों में देशहित और जनहित की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक न किसी कागजी कानून से और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्थिति बदल सकेगी। यह सही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी कोशिश काफी नहीं। समग्रता में काम होता नहीं दिख रहा। फिर, राजनीति में लोग अब स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहे हैं। सबको अपनी जेब और तिजोरी की चिंता है। ऐसे में, सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता, हमें अब किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए!

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कठोर फैसला लिया, लेकिन सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने इसका भी दम निकाल दिया, जिसके कारण देश को न माया मिली और न राम, यानी नोटबंदी से न आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला धन विदेश से भारत आ सका। आजादी के बाद से अब तक सत्तारूढ़ सभी पार्टियों ने कमोबेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन उस पर असली वार शायद ही कभी किया गया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, तो आज देश में भ्रष्टाचार कोढ़ न बनता और न सुशासन की हवा निकलती।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

सुशासन दिवस

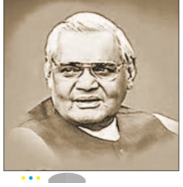

सिद्ध हो रही इस दिन की सार्थकता

यह सही है कि साल 2014 से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है, तब से सुशासन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। बीते 11 साल से सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जान पड़ता है। इस दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि देशवासियों का जीवन भी आसान बनाया। यही कारण है कि अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है, क्योंकि हम जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने को प्रतिबद्ध हैं।

सुशासन की दिशा में किस कदर काम हो रहे हैं, इसकी झलक सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन योजनाओं में न सिर्फ गरीबी से निपटने की मंशा है, बल्कि सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर भी जोर है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसका असर उनकी जीवनशैली पर पड़ा है और वे अब हाशिये पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा में शुमार होने लगे हैं। यही वजह है कि बीते वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हो सके। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंच सका है। हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, यह सरकार ने बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

यह सही है कि सुशासन का अर्थ है, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी तरीके से सरकार चलाना, पर शासन व्यवस्था की बेहतरी इसमें भी निहित है कि सरकारी योजनाएं असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। राजीव गांधी का वह बयान शायद ही कोई भूल सकता है, जब उन्होंने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए रुपये व पैसे का उदाहरण किया था। आज स्थिति बदल गई है। अब सीधे बैंक खातों में योजनाओं की राशि पहुंचती है, जिससे भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, हर नागरिक को समान अवसर मिल पा रहा है, जिसका लाभ समाज को हो रहा है। इन सबसे सुशासन जैसे दिवसों की सार्थकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आम लोगों को बेरोकटोक उनके अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो इसे सुशासन ही समझिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-23

अटल जी का अनुकरणीय सांसद-धर्म

डा. ब्रजेश कुमार तिवारी

विपक्ष में रहते हुए भी सत्तापक्ष के मन में स्थान कैसे बनाया जाता है, यह अटल जी के व्यक्तित्व से सीखना होगा

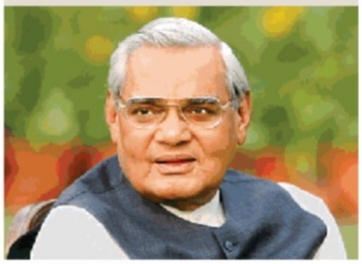

भारतीय राजनीति को बदलने वाले नेता ● फाइल

एक ऐसे समय में जब लगातार लोकतांत्रिक अवमूल्यन हो रहा है और सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच दरार बहुत गहरी हो चुकी है, तब अटल जी की जन्म शताब्दी में उनका स्मरण अत्यंत जरूरी हो जाता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल राजनीतिज्ञ, संवेदनशील प्रशासक, निःस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, भाषाविद्, कवि, पत्रकार, लेखक और बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में बदलाव 'घोषणापत्र' से नहीं, बल्कि उन फैसलों से आता है, जो शासन की प्राथमिकताओं को स्थायी रूप से बदल देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने विकास को 'परियोजनाओं की सूची' से निकालकर 'राष्ट्रीय क्षमता' के रूप में देखना सिखाया। उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए, जिन्होंने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका परिवर्तनकारी दृष्टिकोण दूरसंचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित होता है।

प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई। वाजपेयी की वाक्पटुता घरेलू मंच तक ही सीमित नहीं थी। 1977-79 के दौरान भारत के विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने 32वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण हिंदी में भी दिया। अटल जी ने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और जिनका लाभ आज भी हर भारतीय को मिल रहा है। उनके शासनकाल में प्राकृतिक आपदाओं और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 8.4 प्रतिशत से ऊपर बनी रही, मुद्रास्फीति चार प्रतिशत से नीचे रही और विदेशी मुद्रा भंडार भी संतोषजनक स्थिति में था। इस सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का लाभ यूपीए-1 सरकार को मिला।

शिक्षा के क्षेत्र में वाजपेयी का योगदान सर्व शिक्षा अभियान के रूप में मील का पत्थर साबित हुआ, जो 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाली सामाजिक योजना है। 2000 में जहां लगभग 40 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, वहीं 2005 तक यह संख्या घटकर लगभग 10 प्रतिशत रह गई। उन्होंने इस योजना को प्रचारित करने वाली थीम लाइन 'स्कूल चले हम' स्वयं लिखी थी। अटल जी को जनजातीय मामलों के मंत्रालय, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विभाग और सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय मंत्रालय में परिवर्तित करने तथा नए विभागों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। 'जय जवान-जय किसान और जय विज्ञान' का नारा देने वाले अटल जी ने चंद्रयान-1 परियोजना को भी स्वीकृति दी। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। उनकी ठोस उपलब्धियों में भारत की हाईवे-कल्पना का राष्ट्रीयकरण भी है। उन्होंने 'इन्फ्रास्ट्रक्चर को राजनीति की भाषा' बना दिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद की और यह एनडीए सरकार का एक गौरव बना।

सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग ही नहीं, बल्कि उनके दौर में यह समझ भी मजबूत हुई कि विकास तब तक अधूरा है, जब तक गांव बाजार, स्कूल और अस्पताल से नहीं जुड़ते। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को शहरों से जोड़ा गया। वाजपेयी का दृढ़ विश्वास था कि निर्माण और बुनियादी ढांचे की उन्नति आर्थिक विकास के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। उनके नेतृत्व में तीन मार्च, 1999 को नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई, जिससे इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया और देश में सस्ते मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ। उनके प्रमुख नीतिगत निर्णयों में 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम भी शामिल है। उनकी सरकार ने औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पार्कों की स्थापना की और सही मायनों में मेक इन इंडिया की नींव रखी। वाजपेयी सरकार ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों की शुरुआत की, जिससे बैंकों को उनके गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीए) से निपटने में मदद मिली। यह कदम क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना की दिशा में भी पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इससे बैंकों के एनपीए में सुधार हुआ और उनकी बैलेंसशीट मजबूत हुई।

विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष के मन में स्थान कैसे बनाया जाता है, यह अटल जी के व्यक्तित्व से सीखना होगा। उनका सांसद-धर्म हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र 'जीत' से नहीं, बल्कि संस्थाओं की मर्यादा और संवाद की गुणवत्ता से मजबूत होता है। आज यदि राजनीति को ऊंचा उठाना है, तो सबसे पहले संसद को 'शोर का अखाड़ा' नहीं, बल्कि समाधान की पाठशाला बनाना होगा-और यही अटल जी से मिलने वाली सबसे प्रासंगिक सीख है।

(लेखक जेएनयू के अटल स्कूल आफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-16

राष्ट्र प्रेरणा स्थल

लखनऊ में आकार लेता राष्ट्र प्रेरणा स्थल आधुनिक भारत की वैचारिक यात्रा को समर्पित एक ऐसा राष्ट्रीय परिसर है, जहां विचार, राष्ट्रबोध और लोकतांत्रिक चेतना एक साथ सजीव होती है। यहां स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाएं केवल स्मरण के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की तीन सशक्त वैचारिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह स्थल नागरिकों को यह समझाने का माध्यम बनता है कि भारत का लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं, बल्कि उनके विचारों और जीवन मूल्यों से आगे बढ़ता है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सशक्त राष्ट्र की अवधारणा को रेखांकित करती है। उनका जीवन भारत की संप्रभुता और वैचारिक स्पष्टता के लिए सतत संघर्ष का उदाहरण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा 'एकात्म मानववाद' के उस विचार को मूर्त रूप देती है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के संतुलित विकास की परिकल्पना निहित है। यह प्रतिमा सामाजिक समरसता, अंत्योदय और मानवीय गरिमा के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनती है।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लखनऊ में स्थापित होना विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि यह वही नगर है, जिसने उन्हें लंबे समय तक अपना सांसद चुना। अटल जी का व्यक्तित्व लोकतांत्रिक मर्यादा, संवाद, सुशासन और राष्ट्रहित के संतुलन का प्रतीक रहा है। उनकी प्रतिमा लखनऊ और राष्ट्र दोनों के लिए प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनेगी। यह गौरवपूर्ण स्थल शीघ्र ही माननीय नरेन्द्र मोदी के करकमलों से राष्ट्र को अर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की उस सोच का परिचायक है, जहां विकास के साथ विचार, इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को समान महत्व दिया गया है। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश देने वाला है कि सशक्त भारत का निर्माण केवल भौतिक प्रगति से नहीं, बल्कि मजबूत विचार, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतर साधना से होता है।

मुख्य विशेषताएं

- 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ भूमि पर निर्मित।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊँची कांस्य से बनी हुई प्रतिमाएं।
- तीनों महापुरुषों के जीवन तथा उनकी विचारधारा पर आधारित संग्रहालय।
- दो लाख क्षमता का रैली स्थल तथा स्टेज।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम / मनोरंजन हेतु एम्फी थिएटर।
- मेडिटेशन सेंटर, विश्राम केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड तथा कैफेटेरिया की व्यवस्था।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल - संग्रहालय तथा मूर्तियों की विशेषताएं

- कमल के आकार में बना यह भवन 98000 वर्गफुट में फैला है।
- विश्व विख्यात मूर्तिकारों — श्रीराम सुतार तथा मंटू राम द्वारा निर्मित।
- मूर्तियों तथा स्टेज पर प्रोजेक्शन मैपिंग की भी व्यवस्था है, जिससे शाम को जीवंत दृश्य दिखेगा।
- वाचनालय तथा आंतरिक सभा की भी व्यवस्था है, जिसमें भविष्य में कार्यक्रम भी कराए जा सकें।
- सम्पूर्ण परिसर में 1.72 किलोमीटर सिंथेटिक ट्रैक का भी निर्माण कराया है, जिससे आसपास की आबादी को टहलने की सुविधा मिले।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल - संग्रहालय के मुख्य गैलरी

- स्वागत स्थल — हेल्प डेस्क, आगंतुकों के मार्गदर्शन हेतु बड़ा डिस्प्ले स्क्रीन, ऑडियो गाइड।
- संग्रहालय — भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भारतीय राष्ट्रवाद तक की झलक।
- प्रवेश — भारतमाता की प्रतिमा, जो राष्ट्रीय भावना की प्रतीक है।

प्रेरणा गैलरी 1 : श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी

श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेकर राजनीतिक विरासत तक की यात्रा को दर्शाने वाली यह गैलरी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है।

इस गैलरी में निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं—

- उडी चित्रावली
- डिजिटल कियोस्क
- अत्याधुनिक सेट डिज़ाइन
- एनीमेशन तकनीक
- इंटरैक्टिव प्रदर्शनी

यह गैलरी उनके विचारों, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में योगदान को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है।

प्रेरणा गैलरी 2 : पंडित दीनदयाल उपाध्याय

- यह गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारधारा और दर्शन को समर्पित है।
- यहाँ उनके एकात्म मानववाद और राष्ट्रवादी दृष्टि को आधुनिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएँ-**

टच टेबल | प्रोजेक्शन स्क्रीन | विस्तृत इन्फोग्राफिक्स | आकर्षक सेट डिज़ाइन | एनीमेशन आधारित प्रस्तुति

यह गैलरी सामाजिक समरसता और भारतीय विचारधारा को समझने का सशक्त माध्यम है।

प्रेरणा गैलरी 3 : श्री अटल बिहारी वाजपेयी

- यह गैलरी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाती है।
- इसमें उनके जीवन, साहित्य और राजनीतिक योगदान को विशेष रूप से उकेरा गया है।
- **मुख्य आकर्षण-**

जीवन आधारित डियोरामा | कवि एवं पत्रकार के रूप में अभिलेख | राम जन्मभूमि खंड | डिजिटल एल्बम | आधुनिक सेट डिज़ाइन | एनीमेशन प्रस्तुति | सम्मान एवं पुरस्कारों की प्रदर्शनी

यह गैलरी उनके ओजस्वी व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र सेवा को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत करती है।

अटल जी के नाम पर प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएँ

1. अटल पेंशन योजना (APY)
- असंगठित क्षेत्र के लिए वृद्धावस्था पेंशन; 60 वर्ष के बाद सुनिश्चित आय।

2. अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)
- शहरों में पानी, सीवर, हरित क्षेत्र व शहरी ढांचा सुधार।

3. अटल इनोवेशन मिशन (AIM)
- स्कूलों/कॉलेजों में नवाचार, स्टार्ट-अप व अटल टिंकरिंग लैब्स।

4. अटल भूजल योजना (Atal Jal)
- भूजल संरक्षण व जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी।

5.अटल स्वास्थ्य बीमा/अटल आयुष्मान संदर्भ योजनाएँ (राज्य-स्तर)
- गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा (राज्य अनुसार नाम/रूप बदलता है)।

कठोर राजनीति को संवेदना से सींचते रहे अटल बिहारी

कलराज मिश्र | पूर्व राज्यपाल, राजस्थान

किसी भी देश-समाज में अपने विचार, आचरण और संवेदना से पूरे युग की दिशा निर्धारित करने वाले विरले ही लोग होते हैं। आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक ऐसे ही राष्ट्रपुरुष के रूप में दर्ज है। अटल जी राजनीति में थे, पर राजनीति से कहीं ऊपर दिखाई देते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से सार्वजनिक जीवन में गरिमा, संवाद और संतुलन का भाव स्थापित हो जाता था। जनता उन्हें इसलिए नहीं मानती थी कि वह प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए कि वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रनायक थे।

मैंने अटल जी को केवल सरकार के मुखिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में अनुभव किया, जिनकी सोच राष्ट्रहित, लोक-कल्याण और मानवीय मूल्यों पर आधारित थी। उनका यह कथन कि 'सरकारें आएंगी, जाएंगी; पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए।' यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उनके सार्वजनिक जीवन का सार था। यही भाव उनके प्रशासनिक व राजनीतिक निर्णयों की नींव बना। अटल जी के सार्वजनिक जीवन का मूल आधार सुशासन था। उनके लिए शासन का अर्थ केवल फाइलों का निपटारा नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना था। उनके नेतृत्व में विकास एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प बना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ने देश की दूरियां पाटते हुए आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी, तो उदारीकरण को आगे बढ़ाकर उन्होंने भारत को आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में खड़ा किया। उनके निर्णयों में स्पष्टता थी, दूरदृष्टि थी और सबसे अहम, उनमें देश के अंतिम व्यक्ति का हित निहित था। आज भी उनकी सरकार द्वारा आरंभ अनेक योजनाएं देश की प्रगति की मजबूत आधारशिला बनी हुई हैं।

उनका यह कथन कि 'सरकारें आएंगी, जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए'- उनके पूरे जीवन का सार था। जयंती पर विशेष :

राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में अटल जी ने असाधारण साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। पोखरण के परमाणु परीक्षणों ने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही, यह भी उतना ही सत्य है कि शक्ति के साथ शांति का संतुलन उनकी राजनीति का मूल स्वभाव था। लाहौर की बस यात्रा और संवाद की पहल प्रमाणित करती है कि वह टकराव नहीं, समाधान में विश्वास रखते थे। इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का उनका विचार आज भी भारत की समावेशी और मानवीय राजनीति का नैतिक आधार है।

राजनीतिक दृष्टि से अटल बिहारी वाजपेयी अद्वितीय थे। वह विरोध को लोकतंत्र की शक्ति मानते थे, न कि उसकी दुर्बलता। संसद में उनका आचरण और वाणी मर्यादा की उच्चतम मिसाल हैं। असहमति में भी सम्मान और संवाद बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इसी संतुलन ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक बनाया। अटल जी के व्यक्तित्व का सबसे कोमल और मानवीय पक्ष उनका कवि हृदय था। सत्ता के शोर और राजनीति की कठोरता के बीच उनकी कविता संवेदना, आत्म-चिंतन और राष्ट्रप्रेम की निर्मल धारा थी। वह शब्दों के माध्यम से राष्ट्र की आत्मा से संवाद करते थे। उनकी पंक्तियां आज भी मन को स्पर्श करती हैं और साहस देती हैं- *हार नहीं मानूंगा/ रार नहीं ठानूंगा/ काल के कपाल पर/ लिखता मिटाता हूं/ गीत नया गाता हूं।* ये पंक्तियां केवल कविता नहीं हैं, बल्कि एक राष्ट्र को निरंतर उठ खड़े होने का संदेश हैं।

प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी अटल जी का स्वभाव सरल और आत्मीय रहा। वह कार्यकर्ता के दर्द को भी समझते थे और आम नागरिक की चिंता को अपनी चिंता मानते थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, बल्कि उन मूल्यों की स्वीकृति थी, जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान किसी एक कार्यकाल या एक निर्णय तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, राजनीति को मानवीय गरिमा से जोड़ा और यह सिखाया कि शक्ति के साथ संवेदना और विकास के साथ समरसता कैसे चल सकती है! वह ऐसे नेता थे, जिन्होंने भविष्य की ओर देखते हुए देश को उसकी जड़ों से जोड़े रखा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विजय हजारे ट्राफी में वैभव, सकीबुल गनी और आयुष लोहारुका के शानदार शतक

क्रिकेट में बिहार का विश्व रिकार्ड

574 रन विजय हजारे ट्राफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए बिहार की टीम ने

50 ओवर के क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया

32 गेंदों में सकीबुल ने जड़ा शतक, लिस्ट ए में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बने

190 रन बना दोहरे शतक से चूके वैभव, झारखंड की तरफ से ईशान का 33 गेंदों में शतक

ईशान का भी शतक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : : वनडे प्रारूप वाले विजय हजारे ट्राफी टूर्नामेंट में बुधवार को कई रिकार्ड ध्वस्त हुए। बिहार के बल्लेबाजों ने बुधवार को अपनी आतिशी पारियों से विश्व कीर्तिमान गढ़ दिया। रांची के जेएससीए ओवल मैदान पर विजय हजारे ट्राफी के प्लेट ग्रुप मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, कप्तान सकीबुल गनी और आयुष लोहारुका की ताबड़तोड़ शतकीय पारियों से बिहार ने 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 574 रन बना दिए। जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम 42.1 ओवर में 177 रन पर सिमट गई। बिहार ने तमिलनाडु के 506 रन के स्कोर के रिकार्ड को तोड़ा, जो उसने 2022 में बनाया था।

बिहार बनाम अरुणाचल में कीर्तिमानों की झड़ी लगी। बिहार ने 50 ओवर के क्रिकेट की किसी प्रारूप का सबसे अधिक रन (574) बनाए। सबसे अधिक रन से जीत (397) हासिल की। 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (190) ने 36 गेंद में शतक जड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही झारखंड के कप्तान ईशान किशन (135) ने 33 गेंद में तो बिहार के कप्तान सकीबुल गनी (128) ने केवल 32 गेंद में शतक जड़ डाला। सकीबुल लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बन गए। वैभव ने 84 गेंदों में 190 रन बनाए। आयुष ने 56 गेंदों में 116 रन बनाए।

15 साल बाद विजय हजारे ट्राफी खेल रहे विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में पहला रन लेते ही लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 16000 रन पूरे करके सचिन तेंदुलकर का रिकार्ड तोड़ा।

संबंधित खबरें • पेज 18 पर

वैभव सूर्यवंशी, कप्तान सकीबुल गनी, आयुष लोहारुका और ईशान किशन • पेट/इंटरनेट मीडिया

पुरुष लिस्ट-ए में बड़ा स्कोर

स्कोर	टीम	साल
574/6	बिहार	2025
506/2	तमिलनाडु	2022
498/4	इंग्लैंड	2022
496/4	सरे	2007

लिस्ट ए में सबसे तेज शतक

गेंद	बल्लेबाज	वर्ष
32	सकीबुल गनी (बिहार)	2025
33	ईशान किशन (झारखंड)	2025
35	अनमोलप्रीत (पंजाब)	2024
36	वैभव सूर्यवंशी (बिहार)	2025

Dainik Jagaran Page No-2

हॉकी स्टार हार्दिक होंगे 'खेलरत्न', 24 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार

खेल अवॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह के नाम की सिफारिश इस साल 'मेजर ध्यानचंद खेलरत्न' पुरस्कार के लिए की गई है। युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए दिए गए हैं।

हार्दिक टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। इस साल एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में भी वह शामिल थे।

बैठक में फैसला : बुधवार को चयन समिति की बैठक में अर्जुन पुरस्कार के लिए 21 अन्य नाम तय किए हैं। चयन समिति में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया शामिल हैं।

19 वर्ष की देशमुख विश्व कप जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और तेजस्विन शंकर के नाम की भी अनुशंसा की गई है जिन्होंने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था और इस साल एशियाई चैंपियनशिप में भी दूसरे स्थान पर रहे।

चार खिलाड़ी पिछले साल बने थे खेलरत्न

पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरुष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और महिला निशानेबाज मनु भाकर को खेलरत्न से नवाजा गया था। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेलरत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रुपये मिलते हैं जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपये दिए जाते हैं।

पुरस्कारों के लिए इनके नाम की सिफारिश की गई

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न : हार्दिक सिंह (हॉकी)।

अर्जुन पुरस्कार : तेजस्विन शंकर, मोहम्मद अफजल और प्रियंका (तीनों एथलेटिक्स), नरेंदर (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज), दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल और लालरेम्सियामी (दोनों हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खोखो), रुद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी), एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह (नौकायन), अखिल श्योराण और मेहुली घोष (दोनों निशानेबाजी), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती (योग), त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद (दोनों बैडमिंटन) और पूजा (कबड्डी)।

योग खिलाड़ी भी शामिल : खेल मंत्रालय से औपचारिक मान्यता मिलने के पांच साल बाद पहली बार योगासन खिलाड़ी आरती पाल का नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया गया है। आरती राष्ट्रीय और एशियाई चैंपियन हैं। एशियाई खेल 2026 में योगासन नुमाइशी खेल के रूप में शामिल होगा।

दो बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य विजेता राइफल निशानेबाज मेहुली घोष, जिम्नास्ट प्रणति नायक और भारत की नंबर एक महिला बैडमिंटन जोड़ी त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद के नाम की भी सिफारिश की गई है।

Hindustan Page No-23

स्वदेशी पोत 'समुद्र प्रताप' बेड़े में शामिल

कार्रवाई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में ताकतवर पोत शामिल हुआ है। 'समुद्र प्रताप' नाम का पोत आधुनिक हथियारों और रिमोट कंट्रोल गन से लैस है। साथ ही यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी।

नौसेना के लिए अधिकांश जंगी पोतों का निर्माण अब देश में ही किया जा रहा है। जंगी पोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री का उपयोग इस साल बढ़कर 84 फीसदी तक पहुंच गया है। यह पहली बार है जब जंगी पोतों के निर्माण में इतना अधिक स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है। नियम के अनुसार, जिस सामग्री में 50 फीसदी से अधिक स्वदेशी कंटेंट होता है, उसे 'मेड इन इंडिया' माना जाता है। नौसेना के लिए 100 से अधिक जंगी पोत और नौकाएं देश में बनाई जा चुकी हैं।

पोत की लंबाई
114.5 मीटर

चौड़ाई
16.5 मीटर

60% से ज्यादा सामान स्वदेशी

■ समुद्र प्रताप के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत मजबूत

Hindustan Page No-24

पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद

साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आए ही निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे... मगर अफसोस, आज विरले ही लोग होंगे, जो देश और समाज के बारे में गंभीरता से सोचते होंगे ? वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सरकार में आम जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, लेकिन असलियत में हमारे अधिकारी कितने जवाबदेह बने, यह कोई रहस्य नहीं है। आज भी लालफीताशाही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, जिसको खत्म करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कोशिश जमीन पर नहीं दिख रही।

दरअसल, हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। यह सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ऐसे में, सुशासन की ओर भारत भला कैसे बढ़ सकेगा ? आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जवाबदेह शासन-व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लिहाजा, जब तक नेताओं, नौकरशाहों और अन्य हितधारकों में देशहित और जनहित की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक न किसी कागजी कानून से और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्थिति बदल सकेगी। यह सही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कोशिश काफी नहीं। समग्रता में काम होता नहीं दिख रहा। फिर, राजनीति में लोग अब स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहे हैं। सबको अपनी जेब और तिजोरी की चिंता है। ऐसे में, सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता, हमें अब किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए!

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कठोर फैसला लिया, लेकिन सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने इसका भी दम निकाल दिया, जिसके कारण देश को न माया मिली और न राम, यानी नोटबंदी से न आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला धन विदेश से भारत आ सका। आजादी के बाद से अब तक सत्तारूढ़ सभी पार्टियों ने कमोबेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन उस पर असली वार शायद ही कभी किया गया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, तो आज देश में भ्रष्टाचार कोढ़ न बनता और न सुशासन की हवा निकलती।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

सुशासन दिवस

सिद्ध हो रही इस दिन की सार्थकता

यह सही है कि साल 2014 से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है, तब से सुशासन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। बीते 11 साल से सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जान पड़ता है। इस दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि देशवासियों का जीवन भी आसान बनाया। यही कारण है कि अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है, क्योंकि हम जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने को प्रतिबद्ध हैं।

सुशासन की दिशा में किस कदर काम हो रहे हैं, इसकी झलक सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन योजनाओं में न सिर्फ गरीबी से निपटने की मंशा है, बल्कि सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर भी जोर है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसका असर उनकी जीवनशैली पर पड़ा है और वे अब हाशिये पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा में शुमार होने लगे हैं। यही वजह है कि बीते वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हो सके। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंच सका है। हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, यह सरकार ने बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

यह सही है कि सुशासन का अर्थ है, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी तरीके से सरकार चलाना, पर शासन व्यवस्था की बेहतरी इसमें भी निहित है कि सरकारी योजनाएं असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। राजीव गांधी का यह बयान शायद ही कोई भूल सकता है, जब उन्होंने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए रुपये व पैसे का उदाहरण किया था। आज स्थिति बदल गई है। अब सीधे बैंक खातों में योजनाओं की राशि पहुंचती है, जिससे भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, हर नागरिक को समान अवसर मिल पा रहा है, जिसका लाभ समाज को हो रहा है। इन सबसे सुशासन जैसे दिवसों की सार्थकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आम लोगों को बेरोकटोक उनके अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो इसे सुशासन ही समझिए।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-18

कुछ अलग | नई नीति में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर जोर, निजी स्टेशन खोलने वालों को डेढ़ गुना तक मिलेगा अनुदान

बिहार की नई परिवहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को परिवहन विभाग ने नई ईवी (इलेक्ट्रिकल व्हीकल) नीति बनाने का निर्णय लिया है। नई नीति में बिहार में चार्जिंग स्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से मौजूदा समय की तुलना में डेढ़ गुना तक अधिक अनुदान दिया जाएगा। प्रस्तावित नीति को जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष ले जाने की तैयारी है।

अधिकारियों के अनुसार प्रखंड परिवहन योजना सहित अन्य को एकीकृत कर पर्यावरण अनुकूल योजना लायी जाएगी। उस पर मंथन कर रहा है कि ईवी खरीद पर ही अनुदान दिया जाए। इससे न केवल पर्यावरण का संतुलन कायम होगा बल्कि लोगों में डीजल व पेट्रोल से हटकर ईवी गाड़ियों की खरीद के प्रति ललक भी बढ़ेगी। ईवी गाड़ियों की संख्या के अनुसार राज्य में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अभी पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने शत-प्रतिशत राशि मुहैया कराई है।

अब परिवहन विभाग ने तय किया है कि सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक देय होगी। कोटि एक में एसी चार्जर में पहले 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीदारी पर 75 फीसदी और 10 हजार रुपए अनुदान मिलेगा। लेकिन यह 50 हजार से अधिक नहीं होगा। एसी चार्जर दो में पहले 300 चार्जर में 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं, डीसी चार्जर में पहले 300 चार्जर के लिए मशीन खरीद पर 75 फीसदी और 25 हजार अनुदान लेकिन अधिकतम डेढ़ लाख, सीसीएस में प्रथम 60 चार्जर के लिए 50 फीसदी और एक लाख लेकिन अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा।

राज्य कैबिनेट में जल्द पेश होगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने को नई ईवी नीति बनकर लगभग तैयार है। इसमें चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस पर अनुदान दिया जाएगा।
- राज कुमार, सचिव, परिवहन विभाग

पांच कार की जगह तो चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे

बिहार में निजी चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। आवासीय भवनों के मालिकों, आवासीय कल्याण संघ व सहकारी गृह निर्माण समितियों के माध्यम से निजी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिनके पास न्यूनतम पांच कार लगाने का स्पेस होगा, वे एसी चार्जर श्रेणी का चार्जिंग स्टेशन बना सकेंगे। विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गैर आवासीय भवन, बाजार संघों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय, लोक उपक्रमों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

Hindustan Page No-3

सूबे में अगले पांच वर्षों में दोगुना सब्जी उत्पादन का लक्ष्य : मंत्री

कहा, बिहारी तरकारी का ब्रांड बने बिहार फ्रेश, कोई खेत खाली नहीं रहे

कार्यशाला

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में प्रतिवर्ष 170-180 लाख मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 9 प्रतिशत है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 400 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कोल्ड चेन और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती दी जाएगी। बिहारी तरकारी का ब्रांड बिहार फ्रेश बने।

कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को मीठापुर कृषि भवन में सब्जी से समृद्धि, आत्मनिर्भर किसान विषय पर आयोजित कार्यशाला में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए धान-गेहूं के साथ सब्जी, फल, फूल और औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए। यह प्रयास हो कि बिहार का कोई भी खेत खाली न रहे। हर किसान आत्मनिर्भर बने। बिहार का अनाज, तरकारी हर थाली तक पहुंचे। आधुनिक अनुसंधान, उन्नत बीज, नई तकनीक और नवाचार सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाएं। कहा कि फसल कटाई के बाद 20 से 40 प्रतिशत तक की क्षति किसानों की आय पर सीधा प्रभाव डालती है। वर्तमान में राज्य की कोल्ड स्टोरेज क्षमता 13 लाख मीट्रिक टन है, जबकि वास्तविक आवश्यकता 40 लाख मीट्रिक टन की है।

प्रखंड स्तर तक कोल्ड-चेन, पैक हाउस, ग्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना अब हमारी प्राथमिकता है। प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि बिहार में सब्जी क्षेत्र का विस्तार किसानों की स्थायी आय वृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने तीन फसली खेती, उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज, विशिष्ट पहचान वाली सब्जियों और प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया। मौके पर विशेष सचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, वेजफेड एमडी डॉ. गगन, पीपीएम निदेशक संतोष कुमार मौजूद रहे।

मीठापुर कृषि भवन में बुधवार को सब्जी से समृद्धि, आत्मनिर्भर किसान विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते कृषि मंत्री राम कृपाल यादव। मौके पर प्रधान सचिव पंकज कुमार और विशेष सचिव डॉ. वीरेंद्र प्रसाद यादव।

फसलों-सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाएं: चौरसिया

पटना। किसान धान, फल और सब्जियों की उन्नत किस्मों एवं तकनीकों को अपनाएं। इससे उनकी आय बढ़ेगी। दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आईसीएआर पटना में चल रहे दो दिवसीय किसान मेला के समापन के अवसर पर ये बातें कहीं। उन्होंने विकसित भारत-रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 के महत्व पर भी काश डाला। संस्थान के निदेशक डॉ. अनूप दास ने अधिक से अधिक किसानों को संस्थान से जुड़ने का आह्वान किया। आईसीएआर किसानों की आजीविका सुदृढ़ीकरण, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। विशिष्ट अतिथि बिहार पशु विज्ञान विवि के निदेशक (प्रसार शिक्षा) डॉ. निर्मल सिंह दहिया ने मृदा स्वास्थ्य पर जोर देते हुए गाय के गोबर एवं गोमूत्र का खाद के रूप में सदुपयोग करने की सलाह दी।

Hindustan Page No-12

ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर प्रहार

साल 2025 में भारत ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक पर सीधा वार किया। पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इसके अलावा, 2025 नक्सलियों के खात्मे, महाकुंभ जैसे विशाल सांस्कृतिक आयोजनों के लिए याद किया जाएगा। प्रौद्योगिकी से लेकर बुनियादी ढांचे तक, भारत ने इस वर्ष आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए।

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इस तस्वीर ने पूरे देश का दिल तोड़ दिया। हनीमून पर गई दुल्हन अपने पति के शव के पास बिलखती दिखी। जवाब में भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकाने तबाह किए।

दुनिया को दिया सख्त संदेश नागरिकों पर हमले नहीं सहेंगे

पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इस साल के सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक रहा। अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम घूमने आए पर्यटकों पर आतंकियों ने कायरतापूर्वक गोलियां बरसाईं। 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी। इस हत्या ने देशभर में लोगों को झकझोर दिया।

इसके जवाब में भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति सख्त है और देश के नागरिकों पर हमला युद्ध माना जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों की बदलती रणनीतिक क्षमता और दृढ़ संकल्प उदाहरण था। इसने भारत की जवाबी मिसाइल हमले और सैन्य ताकत को प्रदर्शित किया।

सिर्फ 22 मिनट में ठिकाने नष्ट: इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 22 मिनट में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंक के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया। सेना का हमला बेहद सटीक था। भारत ने यह भी साबित किया कि भारतीय सेना के पास आधुनिक खुफिया जानकारी और सटीक लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। आतंकियों को बड़ा नुकसान हुआ।

पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब: आतंकी ठिकानों पर हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले किए। भारतीय सेना ने इस हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अपनी हार सामने देखकर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का आग्रह किया।

प्रयागराज महाकुंभ मेला

13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बना। इस मेले में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक था। श्रद्धालुओं को लाने और ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें, सुरक्षा और स्वच्छता अभियान चलाए गए, लेकिन मौनी अमावस्या पर भगदड़ ने सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया।

धार्मिक व अन्य आयोजनों में भगदड़ ने झकझोरा

1 — 9 जनवरी
आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुबह के समय मची भगदड़ में छह लोगों की मौत हो गई। संकरी गलियों के कारण भीड़ में लोग वहीं फंसे रह गए।

2 — 29 जनवरी
प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान संकरे रास्ते पर श्रद्धालु फंस गए और बैरिकेड के झुकने से गिरावट और अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 30 की मौत हो गई।

3 — 15 फरवरी
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के पास भगदड़ मच गई। ट्रेन में देरी की वजह से भारी भीड़ प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई थी। हादसे में 18 लोगों की दुखद मौत हो गई थी।

4 — 3 मई
गोवा के शिरगांव गांव, बिचोलिम में लैराई जात्रा उत्सव के दौरान भीड़ ने अस्थायी बैरिकेड्स को तोड़ दिया। अग्नि अनुष्ठान के पास भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

5 — 4 जून
बेंगलुरु में आरसीबी की पहली आईपीएल जीत उत्सव के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

6 — 27 जुलाई
हरिद्वार में मानसा देवी मंदिर तीर्थयात्रा के दौरान भगदड़ मचने से आठ लोगों की मौत हो गई। खड़े और संकरे रास्ते पर रुकावट आने से भीड़ आगे नहीं बढ़ पाई।

7 — 27 सितंबर
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की राजनीतिक रैली के दौरान अपेक्षा से अधिक भीड़ की वजह से भगदड़ मची। इस हादसे में 39 लोगों की मौत हुई।

8 — 1 नवंबर
कासिबुग्गा, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अत्यधिक भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में मची भगदड़ में नौ लोगों की मौत हो गई। बचाव में देरी से भी लोगों की जानें चली गईं।

बड़ी उपलब्धियां

नक्सलवाद पर चोट, कई इनामी नक्सली मारे

2025 में भारत में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हुई। 270 से अधिक नक्सली मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए और 1200 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े ऑपरेशन जैसे 'ब्लैक फॉरेस्ट' और अबूझमाड़ एनकाउंटर में कई शीर्ष कमांडर ढेर हुए। इनमें प्रमुख रूप से सीपीआई (एम) के महासचिव बसवराज भी शामिल हैं।

- **केशव राव** (1.5 करोड़)
- **माड़वी हिडमा** (1.8 करोड़)
- **मोडेम बालकृष्ण** (1 करोड़)
- **प्रयाग मांझी** (1 करोड़)
- **जयराम उर्फ चलपति** (1करोड़)

सुरक्षाबलों की चौतरफा कार्रवाई ने नक्सली संगठनों की कमर तोड़ दी है। नक्सलियों के लगातार खात्मे की वजह से देश के कई क्षेत्र अब नक्सल-मुक्त घोषित हो चुके हैं।

मुंबई हमलों का साजिशकर्ता दिल्ली लाया गया

2008 मुंबई आतंकी हमले (26/11) के प्रमुख साजिशकर्ता और डेविड हेडली के सहयोगी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर अप्रैल 2025 में भारत लाया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अंतिम अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद 9 अप्रैल को उसे एनआईए को सौंपा गया। उसे स्पेशल प्लेन से दिल्ली लाया गया। भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसपर केवल मुंबई हमलों से जुड़े आरोपों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। एनआईए ने पीड़ितों के लिए राणा को फांसी की मांग की है। यह बड़ी कूटनीतिक सफलता है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मील का पत्थर है।

अंतरिक्ष में शुभांशु ने फहराया तिरंगा

भारतीय वायुसेना के पायलट शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम मिशन-4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। राकेश शर्मा के बाद यह पल भारत के लिए बेहद गर्व का अवसर था। इस मिशन के दौरान उन्होंने माइक्रो-ग्रेविटी में विज्ञान प्रयोगों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत के भविष्य के 'गगनयान' मिशन और खुद के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के सपने को नई मजबूती मिली।

इंडिगो एयरलाइंस संकट: हजारों उड़ानें रद्द हुईं, लाखों यात्री प्रभावित

दिसंबर महीने की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ने गंभीर परिचालन संकट का सामना किया। इस दौरान हजारों उड़ानें रद्द हुईं, जिससे देशभर में लाखों यात्री प्रभावित हुए। एयरपोर्टों पर लंबी कतारें, देरी और यात्रियों का गुस्सा आम दृश्य बन गया। यह भारत के एविएशन सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। पायलट ड्यूटी नियमों में बदलाव की इंडिगो ने तैयारी नहीं की, जिससे क्रू की कमी हो गई। दिसंबर के पहले सप्ताह में 4-5 हजार से अधिक उड़ानें रद्द हुईं। 5-10 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। कई यात्री घंटों-दिनों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। लोग शादियों, अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंच पाए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित थे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत

फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दो-तिहाई बहुमत हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव और भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती को दर्शाती है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, सीएम केजरीवाल सहित कई बड़े नेता हार गए।

घटनाओं ने चौंकाया

लाल किला के पास धमाके से दहली दिल्ली

10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के निकट एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। धमाका शाम करीब 6:52 बजे हुआ था। कार में अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था।

जांच में जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से लिंक सामने आए हैं, और फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के साथ कनेक्शन जुड़ा है। एनआईए और दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानकर जांच शुरू की, जिसमें कई गिरफ्तारियां हुईं। घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से मुलाकात की और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का वादा किया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर सख्ती के लिए सरकार को फटकार लगाई। 11 सालों में पहली बार दिल्ली में इस तरह का धमाका हुआ था।

अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा

अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान टेकऑफ करते ही हादसे का शिकार हो गया। 12 जून 2025 को हुए इस हादसे में 260 से अधिक लोगों की मौत हुई। 242 लोगों को लेकर लंदन के लिए उड़ा विमान कुछ ही समय के बाद क्रैश कर गया, इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई जबकि चमत्कारिक रूप से एक व्यक्ति बच गया। हादसे का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ, जमीन पर भी 19 लोग मारे गए और 67 घायल हुए। यह घटना 2025 की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिनी गई। हादसे से गंभीर सवाल भी खड़े हुए।

अगले साल के राजनीतिक घटनाक्रम का असर वर्ष 2029 पर होगा

विशेषज्ञ की राय

प्रो. स्वर्ण सिंह
विश्लेषक

भारत 'एक देश, एक चुनाव' की तैयारी में है, किंतु वर्ष 2026 की एक प्रमुख विशेषता राज्य स्तर पर चुनावों का बेहद व्यस्त कार्यक्रम होगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे यह वर्ष राष्ट्रीय दलों के साथ-साथ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये चुनाव 2029 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक प्रभावित करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधनों की संगठनात्मक शक्ति की परीक्षा लेंगे।

राज्यों के चुनावों के अलावा, भारत में राज्यसभा के चुनाव भी होंगे, जहां वर्ष 2026 में 72 सीटों के लिए नवीनीकरण होना है। इन चुनावों का परिणाम नई दिल्ली में संसद की विधायी प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करेगा। मतदाता सूची विवाद भी पिछले कुछ महीनों से जोर पकड़ रहा है। अगले साल कई राज्यों में एसआईआर को लेकर काफी राजनीतिक विवाद बना रहेगा। आने वाले चुनावों की विश्वसनीयता के लिए इस जटिल मुद्दे पर चुनाव आयोग को अपना पक्ष सामने रखना होगा।

2026 के चुनावों के लिए उच्च स्तरीय दौरे, गठबंधनों की वार्ता और लामबंदी अभियान अभी से चल रहे हैं।

उम्मीदें@2026

1 गगनयान मिशन
साल 2026 भारत की वैज्ञानिक शक्ति के लिए ऐतिहासिक होगा। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा मत्स्य 6000'समुद्रयान' मिशन के तहत भारत पहली बार इंसान को समुद्र की 6,000 मीटर की गहराई में भेजेगा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का छठा देश बन जाएगा। इसरो मार्च 2026 तक 7 प्रमुख मिशन्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

2 सेमीकंडक्टर निर्माण
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई प्लांट्स 2026 में पहली चिप्स प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। इससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत होगा।

3 ब्रिक्स प्रेसिडेंसी
भारत 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभालेगा, जिसमें 100 से अधिक मीटिंग्स पूरे देश में होंगी। यह ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने और डिप्लोमैसी के लिए बड़ा मौका होगा।

4 तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
आईएमएफ, एडीबी सहित अन्य संस्थाओं का अनुमान है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% से 6.6% तक रहेगी। यह चीन से आगे तेज गति वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत का बढ़ना जारी रहेगा।

5 रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व
फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक्सरसाइज मिलन और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जैसे बड़े इवेंट्स हैं। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत करेंगे। डिफेंस में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

6 एआई और डिजिटल इंडिया
फरवरी में दिल्ली में 'इंडिया एआई इम्पैक्ट का आयोजन होगा। जिसका उद्देश्य खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा में एआई के समावेश के लिए 'सॉवरेन एआई'क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा अगले साल तक देश के हर गांवों में 5जी कनेक्टिविटी का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है।

Useful For Mains

शहरों के शोर से सेहत पर संकट

भारत में शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अब यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है।

रोहन सिंह

देश में शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अब यह केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। वर्ष 2000 में सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम लागू किए, जिनके अंतर्गत अस्पतालों, स्कूलों और न्यायालयों के आसपास के क्षेत्रों को शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शोर का स्तर दिन में पचास डेसीबल और रात में चालीस डेसीबल से कम रखना था, जैसा कि नियमों की अनुसूची में निर्धारित है। मगर व्यावहारिक तौर पर इन मानकों का शायद ही कभी पालन हो पाया। विभिन्न सर्वेक्षण बताते हैं कि ढाई दशकों का समय बीतने के बाद भी देश के कई शहर पहले से कहीं अधिक शोरगुल वाले हो चुके हैं। सरकार की ओर से घोषित 'शांत क्षेत्रों' में भी ध्वनि प्रदूषण मानकों से कहीं ज्यादा रहता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दस राज्यों में 82 स्टेशनों के साथ 'नेशनल एंबियंट नाइज मानिटरिंग नेटवर्क' शुरू किया था। यह नेटवर्क डेटा तो एकत्र करता है, लेकिन इसके आधार पर कोई वास्तविक समय पर नियामक कार्रवाई नहीं होती। भारत के पास अब नियम और निगरानी दोनों हैं, लेकिन मापने योग्य 'शांति' नहीं है। चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगर आज पहले से कहीं अधिक शोरगुल वाले हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत निगरानी के अधीन 'शांत क्षेत्र' अब ध्वनि प्रदूषण से रहित वास्तविक सार्वजनिक स्वस्थ क्षेत्रों के बजाय केवल नीतिगत प्रतीक बनकर रह गए हैं। इसे संस्थागत विफलता कहा जाएगा या समन्वय की कमी?

दरअसल, मूल समस्या विभिन्न एजंसियों के बीच समन्वय की कमी में निहित है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्थापित मंच के माध्यम से ही डेटा एकत्र करते हैं। मगर नगर निकायों, यातायात पुलिस, स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय प्रशासन के साथ कोई एकीकृत तालमेल नहीं है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को अनिद्रा, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ने की कोई समन्वित प्रणाली भी मौजूद नहीं है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण का डेटा और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव दोनों अच्छी तरह प्रलेखित हैं, मगर कमी सिर्फ इन्हें जोड़कर आकलन करने वाले एकीकृत ढांचे की है।

'शांत क्षेत्रों' को अब तक मुख्यतः प्रशासनिक अधिसूचनाओं के रूप में देखा जाता रहा है, न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण क्षेत्रों के रूप में। निगरानी उपकरणों का रखरखाव कमजोर है और बजट केंद्रीय स्तर पर सीमित रहता है, क्योंकि प्रवर्तन की संस्थागत जवाबदेही बिखरी हुई है। नतीजा यह है कि कानून और डेटा मौजूद हैं, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है और कार्रवाई नदारद। भारत में शोर केवल सहन ही नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर उसे उत्सव की तरह अपनाया जाता है। शादी-ब्याह के बैंड, मंदिरों के लाउडस्पीकर, लगातार हार्न बजाना और जुलूस ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे नागरिक अनुशासन पीछे छूट जाता है। इस स्वीकृति के कारण लोग यह भूल जाते हैं कि शोर एक स्वास्थ्य समस्या है। शासन की प्राथमिकताएं आम तौर पर

विकास परियोजनाओं की ओर झुकी रहती हैं, इसलिए शोर नियंत्रण नीचे खिसक जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए नियमन अक्सर यातायात, व्यापार और राजनीति से टकराता है, जिससे उसका प्रवर्तन कठिन और अलोकप्रिय हो जाता है।सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को दोहरा चुका है कि प्रदूषण-मुक्त वातावरण

> विभिन्न शहरों में 'शांत क्षेत्र' अधिसूचित करने का वास्तविक मकसद इन क्षेत्रों को शोरगुल से दूर रखने का था। मगर, केवल कागजों में कानून बना देने से ध्वनि प्रदूषण कम नहीं हो सकता, उसे शहरी नियोजन, प्रभावी प्रवर्तन और सामूहिक जागरूकता के माध्यम से गढ़ना पड़ता है। समस्या पुराने नियमों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि वे समय, विज्ञान और शहरी वास्तविकताओं के साथ विकसित नहीं हो पाए। आज शोर केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय गरिमा के अधिकारों से टकराने वाला संकट बन चुका है।

का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है। इसके बावजूद प्रवर्तन कमजोर बना हुआ है, सीमित नगर क्षमता और असंगत पुलिस प्रक्रिया के कारण। कई शहरों में अधिसूचित 'शांत क्षेत्र' आज भी खराब संके जन-जागरूकता और नियमित निगरानी के अभाव में केवल काग मौजूद हैं। देश में 'शांत क्षेत्र' के लिए मानक दिन में पचास डेसीबल में चालीस डेसीबल निर्धारित हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, यातायात शोर दिन में 53 डेसीबल और रात में 45 डे अधिक नहीं होना चाहिए। देश के सभी बड़े शहरों में भारतीय स्वास्थ्य संगठन दोनों के मानकों का उल्लंघन हो रहा है।

शहरों की नियोजन योजनाएं आज भी 'शांत क्षेत्र' को तकनीकी के रूप में देखती हैं, न कि स्वास्थ्य-सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में। इस देश को ऐसी प्रणाली की जरूरत है, जो पर्यावरणीय निगरानी के डेटा और शहरी योजना से जोड़े। उदाहरण के लिए, ध्वनि निषे आंकड़ों को अस्पतालों में दर्ज बीमारियों के बढ़ते दायरे, मानसिक रपट या यहां तक कि स्कूलों के प्रदर्शन संकेतकों से जोड़ा जा ऐसा एकीकरण नीति निर्धारण के केंद्र को केवल 'प्रदूषण नियंत्रण' 'स्वास्थ्य-केंद्रित व्यवस्था' की ओर ले जाएगा। 'शांत क्षेत्रों' बनाने के लिए जरूरी है कि ध्वनि प्रदूषण को सिर्फ नियंत्रित करने बढ़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

इसके अलावा 'शांत क्षेत्रों' को सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण क्षेत्र पुनर्परिभाषित करना होगा। उन्हें केवल 'हार्न वर्जित क्षेत्र' नहीं अस्पतालों, स्कूलों और संवेदनशील आबादी वाले इलाकों की रक्षा शहरी स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करना होगा। संस्थागत दा समन्वय को मजबूत करने की जरूरत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निगरानी तक सीमित न रखकर उसे अंतर-एजंसी प्रोटोकाल बनाने, लागू करने और स्वास्थ्य-आधारित मानक तय करने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका अंतर-विभागीय समन्वय, नीति और स्वास्थ्य-आधारित मानकों के विकास तक विस्तृत होनी चाहि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी तमाम एजंसियों के काम करने के तरीकों आवश्यक है। तभी शोर को कम करने का प्रयास एक सरकारी आदेश निकलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का मूल सिद्धांत बन सकेगा।

देश में 'शांत क्षेत्र' अधिसूचित करने का वास्तविक मकसद इन शोरगुल से दूर रखने का था। मगर, केवल कागजों में कानून बना देने प्रदूषण कम नहीं हो सकता, उसे शहरी नियोजन, प्रभावी प्रवर्तन और जागरूकता के माध्यम से गढ़ना पड़ता है। समस्या पुराने नियमों की न इस बात की है कि वे समय, विज्ञान और शहरी वास्तविकताओं विकसित नहीं हो पाए। आज शोर केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं र यह स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय गरिमा के अधिकारों से टकराने व बन चुका है। मजबूत निगरानी और जवाबदेही के बिना 'शांत क्षे सरकारी कागजों में उल्लेखित शब्द बनकर रह जाएगा। नियम-व सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा और लापरवाही बरतने जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी होगी। ध्वनि नियंत्रण की प्रक्रिया में संसाधनों के अभाव को दूर करना भी जरू सुधार के बिना न तो ध्वनि प्रदूषण की सही तरीके से निगरानी हो स न ही प्रभावी उपायों को धरातल पर ठीक तरह से उतारा जा सकेगा। अ प्रदूषण रहित वातावरण का अधिकार कोई प्रतीकात्मक अवधारणा न सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों से जुड़ा मसला है।

अरावली को लेकर केंद्र ने राज्यों को जारी किए निर्देश

नए खनन पट्टों पर रोक, संरक्षित क्षेत्र का किया जाएगा विस्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 दिसंबर।

अरावली पहाड़ियों को लेकर उठे विवाद और इसके संरक्षण की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अब पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही खनन का कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा।

दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पहाड़ियों को अवैध खनन से बचाने और संरक्षित करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टा देने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह रोक पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होती है और इसका मकसद इस पर्वत श्रृंखला की अखंडता को बनाए रखना है।

इन निर्देशों का मकसद गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली अरावली को एक लगातार भूवैज्ञानिक क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। इसके अलावा मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई) को यह निर्देश भी दिया है कि वह पूरे

बाकी पेज ८ पर

फाइल फोटो

मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को यह निर्देश भी दिया है कि वह पूरे अरावली में ऐसे और इलाकों की पहचान करे, जहां खनन पर रोक लगाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारें सभी पर्यावरण सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करें।

Jansatta Page No-1

बुनियादी बदलाव से बचती कांग्रेस

आशुतोष झा

देश पर छह दशक तक राज करने वाली पार्टी के पास बीएलए न हों तो दोष नेतृत्व का माना जाएगा

अभी हाल में दो तस्वीरें आईं, जो काफी चर्चा में रहीं। एक में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत पक्ष-विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रही हैं। दूसरी तस्वीर उसके एक दिन पहले आई, जिसमें प्रियंका सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल की सड़कों को लेकर और केरल में अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा कर रही हैं। वैसे तो संसदीय परंपरा में ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन इसका संदेश गूंजता है। विपक्ष सलाह दे सकता है, शक्ति हो तो दबाव बना सकता है, लेकिन सरकार को अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसकी कोशिश खासतौर से मुख्य विपक्ष की ओर से होती रही है।

इससे शायद ही कोई इन्कार करे कि एक मोड़ पर जाकर नेतृत्व ही अहम हो जाता है। वही पार्टी की दिशाएं तय करने लगता है, उसकी विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता से पार्टी की पहचान होने लगती है। वही पार्टी को हराता और जिताता है और भविष्य तय करने लगता है। वर्ष 2025 इस सवाल का बार-बार जवाब देते दिखा। इस वर्ष दो अहम चुनाव हुए। एक देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरा हमेशा से राजनीति का अखाड़ा बने रहे बिहार में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष तो बने ही, पार्टी के अंदर भी उन्होंने प्रभावी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। इन दोनों राज्यों में चुनाव के बाद फिर से स्पष्ट हो गया कि खुद को अपग्रेड करने की उनकी क्षमता कहीं न कहीं लुप्त है। वे कांग्रेस नेता से खुद को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपग्रेड नहीं कर सके। कारण है संवाद की कमी, जिद और अकड़।

राहुल विपक्ष के नेताओं से तारतम्य बनाने में असफल रहे हैं। सरकार से संवाद करना उनके लिए असहज है। संसद के अंदर भी उनका सख्त चेहरा ही दिखता है। पार्टी में संवाद की स्थिति क्या है, यह बार-बार पार्टी नेताओं की ओर से ही सोनिया गांधी को लिखी जा रही चिट्ठी से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में प्रियंका की तस्वीरों ने चर्चा को छेड़ दिया है तो यह असामान्य नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो हर किसी से संवाद में माहिर हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ उनके उन्मुक्त संवाद को देखा जा सकता है। वे उन मुद्दों को छूते हैं, जो जनता को स्पर्श करें। चुनाव के वक्त पार्टी के साथ खड़े होते हैं और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। उनकी ओर से दिखाए जाने वाले इतिहास के कुछ पन्नों से कांग्रेस परेशान जरूर होती है, पर बतौर प्रधानमंत्री उनकी यह जिम्मेदारी भी तो है कि युवाओं को

अवधेश राजपूत

इतिहास याद दिलाएं। सकारात्मक सोचने की अपील करें।

जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था तो लगा था कि कांग्रेस समय और लोगों की अपेक्षा के अनुसार बदलने को तैयार होने लगी है। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दो दिन के शोर-शराबे के बाद विपक्ष भी चर्चा करने और कार्यवाही को सुचारु करने के लिए राजी हो गया। यह सुखद अहसास था, लेकिन मानसिक रूप से बदलाव नहीं हुआ। चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो सार्थक सुझाव दिए जाने चाहिए थे। बजाय इसके चुनाव आयोग के अधिकार को छीनने की मांग ही होती रही। संविधान भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एसआइआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि यह हो ही नहीं। जो सवाल किए गए, उसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी की बात भी आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सरकार ने एक नियम तय किए, जो सरकार का अधिकार है। सरकार के अधिकार को नकारने का क्या अर्थ? युवाओं को तर्क से समझाना होता है, इतिहास से उदाहरण बताना होता है। तभी वे जुड़ते हैं। युवाओं को तो यही समझ आया कि पहले नेता विपक्ष भी कमेटी में नहीं होते थे। अब मोदी सरकार ने लोकसभा के नेता विपक्ष को शामिल कर दिया। यह नियम किसी भी सरकार पर लागू होगा। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी छवि बड़ी बनानी थी। उन्हें राजनीति में अपराधीकरण रोकने की बात करनी चाहिए थी, एक ही स्थान से चुनाव लड़ने के लिए कानून बनाए जाने का सुझाव देना चाहिए था। एसआइआर पर तो अब चुनाव आयोग ने चुनौती दे दी है और कहा कि कुछ राज्यों में एसआइआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। उसे देख लीजिए और कोई आपत्ति हो तो बताइए।

संसद सत्र के दौरान ही सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताते हुए सारे नाम खारिज कर दिए कि उसमें सामाजिक न्याय का ख्याल नहीं रखा गया, पर जब सूची आई तो उसमें आठ में पांच नाम वंचित वर्ग से थे। ऐसी फिसलनों से विश्वसनीयता का संकट खड़ा होता है। हाल में एसआइआर को लेकर कांग्रेस की एक बैठक हुई। उसमें चिंता जताई गई कि कांग्रेस के पास बूथ लेवल एजेंट बहुत कम हैं। देश पर छह दशक तक राज करने वाली पार्टी के पास बीएलए न हों तो दोष नेतृत्व का माना जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाला है और बताते हैं कि तृणमूल के एक नेता ने किसी से कहा कि कांग्रेस की ओर से अगर गठबंधन की बात होगी तो उनसे स्पष्ट कहा जाएगा कि सहयोग कीजिए।

बंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के अंदर जो भाव था बंदे मातरम् उसकी अभिव्यक्ति थी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 11 वर्षों में देश में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा बुलंद हुई है, लेकिन राहुल गांधी को शायद उस चर्चा में रुचि नहीं थी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जो बात कही, वह तर्कसंगत थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत नेतृत्व के कारण होती है। कांग्रेस में यह बात पहले भी कई शीर्ष नेता कह चुके हैं। राज्यों में भी भाजपा मोदी के नाम की गारंटी लेकर उतरती है। यह सच है कि भाजपा की विश्वसनीयता और लोकप्रियता आज के दिन मोदी के नेतृत्व के कारण है। कुछ राज्यों में अलग-अलग नेताओं ने भी नेतृत्व दिया है और बार-बार जीत भी रहे हैं। कांग्रेस को विश्वसनीयता के संकट से बाहर आना ही होगा।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-15

27 यूनिटों में रुक-रुककर उत्पादन हो रहा, वे उद्यमी बैंक के ब्याज और बाजार के कर्ज में डूब चुके हैं।

80 के आसपास ऐसे श्रमिक हैं जिनका आर्थिक तंगी के कारण उत्पादन बंद हो जाने से रोजगार छिन गया है।

29.30 एकड़ में फैली बाजार समिति परिसर ने कोरोना काल में दिया था आपदा को अवसर में बदलने का माडल

57 में से तीन यूनिट विस्थापित हुई, 27 में लग चुका है ताला, शेष 27 यूनिटें बैंक के ब्याज और बाजार के कर्ज में डूबीं

28 जून 2020 को पश्चिम चंपारण के चनपटिया में स्टार्टअप परिक्षेत्र की रखी गई थी नींव, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित स्टार्टअप जोन के उद्यमी कंगाली की कगार पर, घर की नीलामी तक आई नौबत

कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलकर देश को स्टार्टअप का नया माडल देने वाले पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमी आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह बेहतर माडल साबित हो सकता था, लेकिन नीतिगत खामियों और भूमि हस्तांतरण नहीं होने की वजह से यहां के उद्यमी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पांच वर्ष के अंतराल में पूरी संरचना दम तोड़ती नजर आ रही। आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण यूनिटें बंद हो गईं। 57 में से तीन यूनिटें विस्थापित हो गईं। 27 में ताले और शेष 27 अंतिम सांस ले रही हैं। उद्यमी बैंक के ब्याज एवं बाजार के कर्ज में डूब चुके हैं और उनकी संपत्ति की नीलामी की नौबत है। आज जब नए उद्योग, स्टार्टअप और क्लस्टर्स स्थापना की बात होती है तो सवाल उठता है कि पुरानी औद्योगिक संरचनाओं को सहेजे बिना नई की कल्पना-परिकल्पना कितना सही है।

कभी चनपटिया स्टार्टअप जोन में दिखती थी चहल-पहल, अब पसरा है सन्नाटा • जागरण

सूरत, गुजरात, दिल्ली के अलावा ओमान, इराक, दुबई जैसे देशों की कंपनियों में नौकरी करने वाले 57 कुशल श्रमिकों ने लगाई थी यूनिट

चनपटिया स्टार्टअप : कभी माडल का ताज, अब तंगहाली का साया

सुनील आनंद • जागरण

बेतिया: कोरोना आपदा के दौरान रोजी-रोजगार छूट जाने के कारण घर लौटे कुशल कामगारों को मजदूर से उद्यमी बनाने के संकल्प के साथ चनपटिया बाजार समिति के वीरान पड़े 29.30 एकड़ के परिसर में 28 जून 2020 को स्टार्टअप जोन की नींव रखी गई थी। सूरत, गुजरात, दिल्ली, ओमान, इराक और पोलैंड की विभिन्न कंपनियों में नौकरी कर आजीविका चलाने वाले 57 कुशल श्रमिकों ने अपनी यूनिट लगाई। बिहार सरकार की नवप्रवर्तन योजना से 25-25 लाख का लोन लेकर गारमेंट्स समेत अन्य उत्पाद की फैक्ट्री लगाई। महज एक वर्ष में चनपटिया स्टार्टअप जोन के उत्पाद वैश्विक बाजार में दिखने लगे थे। इसी एक वर्ष में उद्यमियों ने 10 करोड़, 45 लाख का कारोबार कर लिया था।

चनपटिया स्टार्टअप जोन सोसाइटी के कोषाध्यक्ष मो. सद्दाम हुसैन बताते हैं कि उत्पाद की उच्च गुणवत्ता और कम कीमत के कारण अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों से आर्डर आ रहे हैं। परंतु, बैंक के ब्याज की भरपाई और आर्थिक तंगी के कारण उद्यमी आर्डर पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। जिन 27 यूनिटों में रुक-रुककर उत्पादन हो रहा, वे उद्यमी बैंक के ब्याज और बाजार के कर्ज में डूब चुके हैं। लाखों खर्च कर आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। उनका कोई खरीदार भी नहीं कि बेचकर बैंक और बाजार के कर्ज से उबर सकें।

बड़ा सवाल: महज चार वर्ष में क्यों कंगाल हुए उद्यमी: होजरी उद्यमी रमेश कुमार बताते हैं कि कोविड संक्रमण काल में लाकडाउन में घर लौटे थे। नौकरी छूटने के बाद आजीविका की चिंता थी। क्वारंटाइन सेंटर में स्किल मैपिंग हुई और तत्कालीन जिलाधिकारी कुंदन कुमार के दूरदर्शी सोच से श्रमिकों को मालिक बनने का अवसर मिला। चूंकि, उस समय मार्केटिंग का बहुत अनुभव नहीं था। नवप्रवर्तन योजना से किसी को 25 लाख तो किसी को 20 लाख का लोन मिला था। इसमें 14 लाख के आसपास की राशि के लिए बैंक की ओर से पांच वर्ष की ईएमआइ फिक्स की गई। शेष राशि उद्यमियों को कैश क्रेडिट के रूप में मिली। प्रायः उद्यमियों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए टर्म लोन की 14 लाख की राशि से आधुनिक मशीनें खरीद लीं। उत्पादन शुरू हुआ तो कैश क्रेडिट के आठ लाख रुपये कम पड़ने लगे। फिर उद्यमियों ने बाजार से कर्ज लेकर उत्पादन शुरू किया और बारी मार्केटिंग की आई। बाजार में व्यापारियों को कम से कम 90 दिनों का क्रेडिट चाहिए था। स्थानीय व्यापारियों को उत्पाद की गुणवत्ता और कम दर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहीं से उद्यमियों के दुर्दिन शुरू हो गए।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का लाभ नहीं: स्टार्टअप जोन सोसाइटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल का कहना है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 का लाभ चनपटिया स्टार्टअप के उद्यमियों को नहीं मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर, 2024 को प्रगति यात्रा के दौरान स्टार्टअप जोन के विस्तार के लिए बाजार समिति की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर टेक्सटाइल से जुड़ीं यूनिटों को उक्त नीति के तहत अच्छादित करने एवं वित्तीय सहायता देने का आदेश दिया था। 10 जनवरी, 2025 को उद्योग विभाग की ओर से इस पर पहल की गई थी, लेकिन अभी तक भूमि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। इस कारण उद्यमियों को अन्य बैंकों से सहायता नहीं मिल रही। हालांकि, बाजार समिति के गोदाम में शेड बनाकर स्टार्टअप जोन के लिए उद्यमियों को पांच वर्ष की लीज दी गई थी। वह अवधि भी अब समाप्त हो गई है।

यदि लाभ मिला होता: दरअसल, चनपटिया स्टार्टअप जोन की अधिकतर यूनिटों की स्थापना 2021 से पूर्व हुई थी। इससे यहां के उद्यमियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर, इसका लाभ इन्हें मिलता है तो पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे मशीनरी और अवसंरचना लागत कम होगी। फ्रेट प्रतिपूर्ति का लाभ मिलने लगेगा। इससे कच्चा माल लाने तथा तैयार उत्पाद भेजने में ट्रांसपोर्ट खर्च पर अनुदान मिलने लगेगा। रोजगार सृजन अनुदान, बिजली शुल्क सब्सिडी, पेटेंट पंजीकरण सहायता, ब्याज अनुदान, कौशल विकास सहायता आदि का लाभ मिलने लगेगा। इससे उद्यमियों की लागत कम होने लगेगी और वे योजना का लाभ लेकर फिर से कंगाली के दौर से उबर सकते हैं।

भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया राज्य स्तर पर जारी: उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रोहित राज का कहना है कि भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है। कृषि विभाग में संचिका भेजी गई है। भूमि हस्तांतरण नहीं होने की वजह से ही चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमियों को उद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उद्योग विभाग की नीति के मुताबिक, उद्यमी की यूनिट जिस स्थल पर संचालित है, या तो वह भूमि उद्यमी की होनी चाहिए या फिर लीज की भूमि है तो कम से कम 13 वर्ष के प्रपत्र हो। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमियों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 के तहत अच्छादित करने एवं वित्तीय सहायता देने की पहल की गई, परंतु भूमि का हस्तांतरण नहीं होने से यह प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है। शीघ्र ही विभाग की ओर से भूमि का हस्तांतरण होने वाला है। उसके बाद चनपटिया स्टार्टअप के उद्यमियों को उद्योग विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा।

स्टार्टअप जोन में कढ़ाई युक्त शाल ने बनाई थी पहचान, अब चमक हो रही फीकी। • जागरण

कुमारबाग में विकसित हो रहा टेक्सटाइल पार्क

चनपटिया स्टार्टअप जोन के उद्यमियों की तंगहाली के बावजूद वहां से चार किमी दूर बियाडा की भूमि कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क में 20 उद्यमियों को यूनिट के लिए भूमि आवंटित की गई है। चार उद्यमियों की यूनिट चालू है। इन उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10-10 लाख का ऋण भी मिला है। ये सभी गारमेंट्स के पुराने कारोबारी हैं। लुधियाना की संजय ऊलेन मिल्स ने यहां गारमेंटस यूनिट लगाने के लिए 20 हजार वर्गफीट का शेड बुक कराया है। दरअसल, यहां करीब तीन लाख वर्गफीट भूमि पर वस्त्र उद्योग की स्थापना हो रही। प्लग एंड प्ले माडल पर बिहार सरकार द्वारा उद्योग भवन का निर्माण भी कराया गया है। फिलवक्त आठ शेड बनकर तैयार हैं। एक में 20 हजार वर्गफीट जगह है। चनपटिया स्टार्टअप जोन में भूमि का किराया एक रुपये चार पैसे की दर से निर्धारित है, जबकि यहां चार रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से महीने का किराया लिया जाता है। उद्यमी निशिकांत कुमार बताते हैं कि यहां भूमि हस्तांतरण की कोई समस्या नहीं है, इसलिए सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में यहां के उद्यमियों को किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

स्टार्टअप जोन को मिला था प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार

21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चनपटिया स्टार्टअप जोन को इनोवेशन के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार को सम्मानित किया था। सम्मान के साथ स्टार्टअप जोन के विकास के लिए 20 लाख रुपये अवार्ड मनी भी मिले। प्रधानमंत्री ने इनोवेशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सराहना की। चूंकि उस वक्त जिलाधिकारी के प्रयास से नव प्रवर्तन योजना से 57 उद्यमियों की यूनिटें क्रियाशील थीं। अत्याधुनिक टेक्नोलाजी युक्त 400 से अधिक मशीनों की स्थापना हो चुकी थी। 15 करोड़ से अधिक का कारोबार भी था। बनारसी साड़ी, स्वेटर, कश्मीरी शाल, सेनेटरी पैड, फुटवियर्स, होजरी, स्टील के बर्तन आदि का निर्माण हो रहा था। देश के विभिन्न राज्यों के जिलों से 847 सिर्फ इनोवेशन के क्षेत्र में एक्सीलेंस अवार्ड के लिए आए प्रस्तावों में से केंद्र सरकार को चनपटिया स्टार्टअप जोन का माडल पसंद आया था।

डेढ़ लाख रुपये की नौकरी गई और अब घर भी दांव पर

चनपटिया वार्ड संख्या तीन निवासी युवा उद्यमी मो. अयूब अंसारी का गारमेंट्स (जींस पैंट) यूनिट बंदी के कगार पर है। बैंक इनके घर को नीलाम करने के लिए नोटिस चस्पा कर रहा है। दरअसल, अयूब इराक में एक गारमेंट्स कंपनी में 1.50 लाख मासिक वेतन पर काम करते थे। उन्हें इंटरनेट मीडिया से चनपटिया स्टार्टअप जोन के बारे में जानकारी मिली थी। घर आकर मां की सेवा की चाहत में उन्होंने नौकरी छोड़ी और 2021 दिसंबर में आकर अपनी यूनिट लगाई। नवप्रवर्तन योजना से उन्हें भी 25 लाख रुपये का लोन मिला। ये अन्य उद्यमियों से बाद में आए, इसलिए इनसे बैंक ने जमानत के लिए मार्गेज (एक वित्तीय समझौता, जिसमें किसी प्रापर्टी, जैसे घर या जमीन, को गिरवी रखकर बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लिया जाता है) के रूप में घर का कागज लिया। अब ईएमआइ की भरपाई नहीं होने के कारण बैंक वसूली के लिए एकमात्र संपत्ति के रूप में घर की नीलाम के लिए नोटिस दे दिया है। अयूब का कहना है कि डेढ़ लाख रुपये की नौकरी गई और अब घर भी जाने वाला है।

1500 श्रमिक काम करते थे, अब मात्र 125 बचे

बिहार से श्रमिकों का प्रवासन रोकने के लिए भी एक माडल बने चनपटिया स्टार्टअप की विभिन्न यूनिटों में कभी 1500 श्रमिक काम करते थे। अभी करीब 125 श्रमिक बचे हैं। उनमें भी 80 के आसपास वैसे श्रमिक हैं जो उद्यमी परिवार के हैं। आर्थिक तंगी के कारण उत्पादन बंद हो जाने से श्रमिकों का रोजगार छिन गया है। मैनाटांड़ के मो. अब्बास गारमेंट्स यूनिट में शर्ट, कुर्ता आदि बनाते हैं। ये दो भाई 22 वर्ष से मुंबई में एक गारमेंट्स कंपनी में नौकरी करते थे। चनपटिया माडल से प्रभावित होकर यहां आए और यूनिट लगाई। नौकरी के दौरान कमाई हुई राशि और दोस्तों से कर्ज लेकर यूनिट खड़ी हो गई। इन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। इनके पास आर्डर भी बहुत है, परंतु आर्थिक तंगी के कारण यूनिट बंद होने की स्थिति में है। दोस्तों से लिए गए कर्ज चुकाने के लिए जमीन बेचनी पड़ी है।

मुख्यमंत्री ने भी किया था स्टार्टअप जोन का निरीक्षण

31 दिसंबर, 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चनपटिया स्टार्टअप जोन में श्रमिक से मालिक बने लोगों के कार्यों को देखने के लिए आए थे। यह माडल उन्हें इतना पसंद आया कि बिहार के सभी जिलों में इस तरह का स्टार्टअप विकसित करने की घोषणा कर दी थी। एक सप्ताह के अंदर अन्य जिलों के अधिकारी भी यहां आए और स्टार्टअप जोन का भ्रमण कर देखा। सीएम ने निरीक्षण के दौरान करीब एक घंटे में अलग-अलग उद्यमियों के उत्पादों का मुआयना किया। उनके बिजनेस माडल को समझा। विदेश से गारमेंट्स के आर्डर की सराहना की। उत्पादन एवं निर्यात में भी सरकारी स्तर पर मदद का भरोसा दिया था।

महंगी मशीन खरीद लीं अब उत्पादन के लिए अर्थाभाव

अर्थशास्त्री डा. सुरेश प्रसाद का कहना है कि किसी भी उद्योग की सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत योजना और अनुशासित क्रियान्वयन जरूरी होता है। बाजार की मांग को समझकर उत्पाद या सेवा देना चाहिए। कुशल प्रबंधन, प्रशिक्षित कर्मचारी, समय पर निर्णय, नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और वित्तीय अनुशासन सफलता की ओर ले जाते हैं। चनपटिया स्टार्टअप में ग्राहक संतुष्टि तो है, लेकिन वित्तीय अनुशासन की कमी रही। उद्योग के लिए बजट बनाना अनिवार्य है, जिसमें मशीन की खरीद से लेकर मार्केटिंग तक का समावेश होता है। यहां उद्यमियों ने बगैर बजट के पहले महंगी मशीनें ही खरीद लीं और अब उत्पादन के लिए अर्थाभाव है।

चनपटिया स्टार्टअप जोन में स्थित सफाना गारमेंट्स में बने डिजाइनर कुर्ते को दिखाते उद्यमी मोहम्मद अब्बास • जागरण

प्रश्न (BPSC Mains GS):
समाचार में वर्णित "चुनपटिया स्टार्टअप/टेक्सटाइल पार्क" के संदर्भ में भारत में स्टार्टअप मॉडल की सीमाओं, कारणों तथा सुधारात्मक उपायों की चर्चा कीजिए।
(शब्द सीमा: 400)

मॉडल उत्तर

भूमिका
- स्टार्टअप्स को रोजगार, औद्योगिकीकरण और स्थानीय विकास का इंजन माना गया।
- बिहार जैसे राज्यों में टेक्सटाइल पार्क/स्टार्टअप से क्षेत्रीय संतुलन की अपेक्षा थी।
- लेकिन चुनपटिया मॉडल में असफलता ने नीति और क्रियान्वयन की कमजोरियों को उजागर किया।

1. चुनपटिया स्टार्टअप/टेक्सटाइल पार्क का संदर्भ
- प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त स्टार्टअप जो मॉडल के रूप में प्रचारित हुआ।
- सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार देने का दावा, परंतु समय के साथ इकाइयाँ बंद।
- 1500 श्रमिकों से घटकर लगभग 125 श्रमिक रह जाना।
- श्रमिक पलायन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव।

2. असफलता के प्रमुख कारण
- **नीतिगत कमजोरियाँ:** दीर्घकालिक विजन का अभाव, केवल उद्घाटन-केंद्रित दृष्टि।
- **बाजार से असंबद्धता:** उत्पाद की मांग, ब्रांडिंग और निर्यात रणनीति कमजोर।
- **वित्तीय समस्याएँ:** कार्यशील पूंजी की कमी, समय पर भुगतान न होना।
- **प्रबंधन अक्षमता:** पेशेवर प्रबंधन, सप्लाई चेन और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव।
- **कौशल अंतर:** स्थानीय श्रमिकों को आधुनिक टेक्सटाइल तकनीक का प्रशिक्षण नहीं।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप:** लॉजिस्टिक्स, बिजली, कच्चे माल और क्लस्टर सपोर्ट कमजोर।
- **सरकारी निर्भरता:** सब्सिडी पर अत्यधिक आश्रित मॉडल, आत्मनिर्भरता का अभाव

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- **रोजगार संकट:** बेरोजगारी और पुनः पलायन।
- **विश्वास ह्रास:** स्टार्टअप नीति पर स्थानीय लोगों का भरोसा कम।
- **राजस्व हानि:** राज्य और स्थानीय निकायों को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं।
- **मानव पूंजी क्षरण:** प्रशिक्षित श्रमिकों का अन्य राज्यों/देशों में जाना।

4. स्टार्टअप इंडिया मॉडल से जुड़ी व्यापक चुनौतियाँ
- "वन-साइज-फिट्स-ऑल" नीति, क्षेत्रीय विविधताओं की अनदेखी।
- स्टार्टअप बनाम MSME के अंतर को न समझना।
- निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र कमजोर।
- क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास की कमी।

5. सुधारात्मक उपाय एवं आगे की राह
- **मार्केट-लिंक्ड मॉडल:** मांग आधारित उत्पादन, निर्यात एवं ई-कॉमर्स एकीकरण।
- **क्लस्टर अप्रोच:** टेक्सटाइल वैल्यू चेन (यार्न–फैब्रिक–गारमेंट) का एकीकरण।
- **पेशेवर प्रबंधन:** PPP मॉडल, निजी विशेषज्ञता की भागीदारी।
- **स्किल डेवलपमेंट:** स्थानीय श्रमिकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण।
- **वित्तीय सुधार:** समयबद्ध क्रेडिट, भुगतान सुरक्षा तंत्र।
- **निगरानी तंत्र:** प्रदर्शन आधारित अनुदान, नियमित ऑडिट।
- **राज्य-विशिष्ट नीति:** बिहार की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप स्टार्टअप नीति।

निष्कर्ष
- चुनपटिया प्रकरण बताता है कि केवल स्टार्टअप टैग पर्याप्त नहीं।
- सतत, बाजार-संबद्ध और मानव-केंद्रित मॉडल ही वास्तविक विकास ला सकता है।
- बिहार जैसे राज्यों में स्टार्टअप को "घोषणा से क्रियान्वयन" की ओर ले जाना अनिवार्य है।